सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-41 अंक 7 | 7 से 21 अप्रैल 2026 | मुख्य संपादक: कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये | पृष्ठ 1

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह की प्रतिमाएं तोड़ना मानवजाति के विरुद्ध एक आपराधिक कृत्य: एसयूसीआई(सी)

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 26 मार्च 2026 को जारी प्रेस बयान में कहा:

"भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1925 का 'काकोरी एक्शन' एक ऐतिहासिक घटना है, जिसने पूरे भारत के स्वतंत्रता-प्रेमी लोगों को प्रेरित किया। इस संघर्ष में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गये थे और इतिहास का एक नया अध्याय रचा था।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के आम लोगों ने इन शहीदों के प्रति गहरी भावना और सम्मान व्यक्त करते हुए 1972 में शहर के केंद्र में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की थीं।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर 23 मार्च को उन प्रतिमाओं को ध्वस्त कर दिया।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का यह कृत्य कोई अलग-थलग घटना नहीं है। यह उनकी लंबे समय से चली आ रही नीति का प्रतिबिंब है, क्योंकि आरएसएस के गुरुजी गोलवलकर के अनुसार, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देशभक्तिपूर्ण नहीं, बल्कि प्रतिक्रियावादी था।

वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम अध्यायों को मिटा देना चाहते हैं।

हम भारत की जनता से आह्वान करते हैं कि वे आगे आयें, भाजपा-नीत उत्तर प्रदेश सरकार की इन आपराधिक कार्रवाइयों का प्रतिरोध करें और निम्नलिखित मांगें उठायें:

1. उन प्रतिमाओं को तत्काल पूर्ण सम्मान के साथ पुन: स्थापित किया जाए।

2) इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को तत्काल दंडित किया जाए।"

भारतीय रेल : कॉर्पोरेट लूट के लिए ललचाने वाला एक प्रमुख क्षेत्र

जब सुदूर उत्तर-पूर्व का कोई गरीब प्रवासी मजदूर दक्षिण की ओर यात्रा करना चाहता है, जहां वह अपेक्षाकृत अधिक आय होने की संभावना देखता है, तो उसके पास ट्रेन यात्रा चुनने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इसी तरह, अपनी मेहनत की कमाई से बचत करने वाला एक बुजुर्ग भक्त तीर्थयात्रा की योजना बनाता है और निश्चित रूप से ट्रेन से यात्रा करना पसंद करता है। इसी प्रकार, एक बेरोजगार युवा या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाला छात्र कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भीड़भाड़ वाले डिब्बे में चढ़ने का साहस करता है। दूसरे राज्य के बेहतर सुविधाओं वाले अस्पताल में इलाज के लिए जाने वाले कई मरीजों के मध्यमवर्गीय परिवार के सदस्य ट्रेन से यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए एक सस्ती, सुलभ और सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे देश के करोड़ों आम लोगों के पास एकमात्र विकल्प ट्रेन यात्रा ही बचा है।

लेकिन यात्रा का यह तरीका अब न केवल बहुत महंगा होता जा रहा है, बल्कि आम लोगों की पहुंच से भी बाहर होता जा रहा है। यह एक सच्चाई है—एक कड़वी सच्चाई—खासकर ऐसे देश में, जहां दो-तिहाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रही है। ऐसे हालात के पीछे एकमात्र कारण केंद्र में एक पर एक सत्तासीन रही बुर्जुआ सरकारों द्वारा अपनायी गई जनविरोधी नीतियां हैं; या और भी सटीक शब्दों में कहें तो, भारतीय रेल जैसे विशाल सार्वजनिक उपक्रम का निजीकरण या कॉर्पोरेटीकरण करने की नीति इसका कारण है।

इस क्षेत्र में विभिन्न सरकारों द्वारा, विशेष रूप से वर्तमान भाजपा शासन के तहत उठाये गए विनाशकारी कदमों पर चर्चा करने से पहले, आइए भारतीय रेलवे के संचालन के विस्तार और विशालता पर एक नजर डालें, जिसका निर्माण भारत के लोगों के खून-पसीने से हुआ है।

सार्वजनिक खजाने से बनी राष्ट्र की जीवन-रेखा

यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय रेलवे के विस्तृत नेटवर्क को ध्यान में रखे बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। आजादी से पहले भी, रेलवे ने न केवल सामंती जमाने के विभिन्न असंबद्ध प्रांतों के लोगों को जोड़ने में मदद की, बल्कि राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य को भी साधने का काम किया। निश्चित रूप से, स्वतंत्र भारत में देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में रेलवे द्वारा निभायी गई भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है, रेलवे देश की धमनी है।

पिछले सात या आठ दशकों के दौरान, रेल कनेक्टिविटी में जबरदस्त वृद्धि हुई है और यह दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणालियों में से एक बन गई है। वर्तमान में भारतीय रेलवे 13,000 से 13,500 यात्री ट्रेनें और

(शेष पृष्ठ 6 पर)

एपस्टीन फाइलों ने उजागर किया पतनशील पूंजीवाद का घिनौना काला सच

पूंजीवाद अब अपने अंतिम दौर में है। इसकी हालत जितनी बिगड़ती जा रही है, यह उतना ही प्रतिक्रियावादी, पूरी तरह से भ्रष्ट और सड़ा-गला होता जा रहा है। यह सड़ांध हर जगह फैल रही है, पूंजीवाद के सेवकों में से कोई भी इससे बच नहीं पा रहा है, चाहे वह इस पतनशील मरणासन्न पूंजीवाद की खुलकर, छिपे तौर पर या गुप्त रूप से सेवा और समर्थन कर रहा हो। बुर्जुआ राजनेताओं से लेकर शिक्षाविदों तक, कुछ जानी-मानी हस्तियां -समाज के ऊपरी या शीर्ष पद पर बैठे लोग इसमें संलिप्त हैं।

एपस्टीन फाइलों के ताजा खुलासे इस बात के साफ सबूत हैं कि ऐसे लोगों का नैतिक-सांस्कृतिक आधार कितना नीचे गिर चुका है। एपस्टीन फाइलों के लाखों पन्नों का खुलासा सिर्फ अपराध का अभिलेख नहीं है, बल्कि यह जर्जर पूंजीवादी समाज का एक सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक -सांस्कृतिक एक्स-रे है।

अब तक रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया है, वह पूरे मामले का खुलासा करता है या नहीं—यह अनिश्चित है। लेकिन जो साफ जाहिर है, वह यह है कि ये फाइलें किसी एक व्यक्ति के अपराधों से कहीं अधिक बड़ी चीज को उजागर करती हैं। एपस्टीन कोई अकेला राक्षस नहीं था, जो इस सड़ी-गली पूंजीवादी व्यवस्था में लगातार बढ़ती दरारों, चौड़ी होती खाइयों से फिसल गया। उसका उदय इस सड़ी-गली सामाजिक- राजनीतिक-आर्थिक प्रणाली के कारण संभव हुआ, जो अन्याय, अपराध, दुराचार, निरंकुशता व अमानवीयकरण के अवतारों को सुक्षा प्रदान कर रही है। यह बयानबाजी नहीं है। यह एक प्रणालीगत बीमारी का निदान है, जो पूंजीवाद में जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों को खा रही है।

कौन था एपस्टीन

एपस्टीन ने 1970 के दशक के मध्य में न्यूयॉर्क के डाल्टन स्कूल में पढ़ाई की, हालांकि वह कभी स्नातक नहीं हुआ। उसकी एक छात्रा के पिता इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एपस्टीन को वॉल स्ट्रीट की निवेश बैंक बेयर स्टर्न्स के एक वरिष्ठ साझीदार से मिलवाया। थोड़े ही समय में एपस्टीन फर्म का साझीदार बन गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, कई मौकों पर एपस्टीन की कारगुजारियों पर बेयर स्टर्न्स ने सवाल उठाया, जैसेकि उसने अपने रिज्यूमे में अपनी शिक्षा के बारे में झूठ बोला और अपनी प्रेमिका के लिए खरीदे गये महंगे गहनों का खर्च कंपनी पर डाल दिया। फिर भी, 1980 तक एपस्टीन की प्रोफाइल बहुत ऊंची थी। एक अंदरूनी जांच में एपस्टीन की गतिविधियां प्रतिभूति और विनिमय आयोग के नियमों का उल्लंघन करती पायी गईं। उसे निलंबित कर दिया गया और जुर्माना लगाया गया, लेकिन उसने गलत काम से इनकार किया और कहा कि वह जांच से "बहुत आहत" है। अंतत: उसने कंपनी छोड़ दी। जाहिर है कि उसके "ऊपर के संबंध" ने उसकी मदद करके उसे बचा लिया।

1982 तक एपस्टीन की धन-दौलत इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी खुद की कंपनी—जे एपस्टीन एंड कंपनी बना ली। एपस्टीन बहुत जल्द ही करोड़पति बन गया। उसने एक सामाजिक दायरा बनाया, जिसमें बेहद अमीर लोग, प्रमुख राजनेता और यहां तक कि राजघराने के लोग भी शामिल थे। बेयर स्टर्न्स में रहते हुए ही वह न केवल न्यूयॉर्क या अमेरिका के, बल्कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों से मेलजोल करने लगा था। 1980 के दशक में एपस्टीन का आकर्षण लगातार अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अभिजात वर्ग, अमीर और ताकतवर हलकों को भी लुभाता रहा। 1990 के दशक में उसने अपना कारोबार अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स के सेंट थॉमस द्वीप से चलाना शुरू कर दिया—जो एक टैक्स हेवन था। बाद में उसने उसी इलाके में ग्रेट सेंट जेम्स नामक एक और द्वीप खरीदा। उसके पास कई निजी जेट भी थे।

वह केवल शेयर बाजार में सट्टेबाजी से और दो सबसे ताकतवर अमेरिकी राष्ट्रपतियों—बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ करीबी संबंधों का लाभ उठाकर ही संपत्ति नहीं बना रहा था। आरोप है कि वित्तीय लाभ की टिप्स देने के अलावा,, नियामक तंत्र का पालन हो या न हो, वह विकृत प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने में भी मददगार था।

2005 में पाम बीच की पुलिस रिपोर्ट ने उसके खिलाफ मानव तस्करी

(शेष पृष्ठ 5 पर)

चार श्रम संहिताओं के खिलाफ पूरे भारत में ट्रेड यूनियनों द्वारा मनाया गया काला दिवस

चार काली श्रम संहिताओं के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र क्षेत्रीय फेडरेशनों व एसोसिएशनों के मंच के आह्वान पर मजदूर-कर्मचारियों ने 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया। उन्होंने काले बैज व काली पट्टियां पहनकर और अनेक स्थानों पर काले झंडे लेकर धरने-प्रदर्शन, साइकिल-मोटर साइकिल जुलूस निकाले और 4 काली श्रम संहिताओं की प्रतियां फूंकी। उन्होंने मालिक-परस्त और श्रमिक-विरोधी इन श्रम संहिताओं को रद्द करने तथा त्रिपक्षीय परामर्श के लिए तुरंत भारतीय श्रम सम्मेलन बुलाने की मांग की।

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) प्रत्याशियों की सूची

कूचबिहार जिला
1. कॉमरेड हितेन बर्मन (मेखलीगंज)
2. कॉमरेड विकाश बर्मन (माथाभांगा)
3. कॉमरेड स्वपन कुमार बर्मन (कूचबिहार उत्तर)
4. कॉमरेड सुमन पंडित (कूचबिहार दक्षिण)
5. कॉमरेड जगदीश चन्द्र अधिकारी (शितलकुची)
6. कॉमरेड विणा पाणि राय (सिताई)
7. कॉमरेड आजिजुल हक (दिनहाटा)
8. कॉमरेड अब्दुस सलाम (नाटाबाड़ी)
9. कॉमरेड भोला साहा (तूफानगंज)

अलीपुरद्वार जिला
10. कॉमरेड किरानी चिक बड़ाइक(कालचीनी)
11. कॉमरेड पियुष कांति शर्मा (अलीपुरद्वार)
12. कॉमरेड वकील चन्द्र भुईंमाली (फालाकाटा)
13. कॉमरेड राम ओरांव(कुमारग्राम)
14. कॉमरेड सुधिष्ट बड़ाइक (मदारीहाट)

जलपाईगुड़ी जिला
15. कॉमरेड प्रिया राय (धुपगुड़ी)
16. कॉमरेड श्यामल राय (मैनागुड़ी)
17. कॉमरेड यशोदा बर्मन (जलपाईगुड़ी)
18. कॉमरेड अनंत राय (राजगंज)
19. कॉमरेड शिवनाथ ओरांव (माल)
20. कॉमरेड राजेश ओरांव (नगराकाटा)
21. कॉमरेड रेणुका राय (डाबग्राम-फुलबाड़ी)

दार्जिलिंग जिला
22. कॉमरेड लक्ष्मी दास (माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी)
23. कॉमरेड डॉ. शाहरियार आलम (सिलीगुड़ी)
24. कॉमरेड प्रकाश लकड़ा (फांसीदेवा)

उत्तर दिनाजपुर जिला
25. कॉमरेड वीरेन्द्रनाथ सिंह (इस्लामपुर)
26. कॉमरेड नवीन चन्द्र सिंह (गोआलपोखर)
27. कॉमरेड अबाई दुल्लाह(चाकुलिया)
28. कॉमरेड सुशांत सिंह (करनदिघी)
29. कॉमरेड प्रबोध सरकार (हेमताबाद)
30. कॉमरेड धुलेश बर्मन (कालीगंज)
31. कॉमरेड माधवीलता पाल (रायगंज)
32. कॉमरेड तपन दास (इटाहार)

दक्षिण दिनाजपुर जिला
33. कॉमरेड रंजीत देब (कुमारगंज)
34. कॉमरेड नमिता महान्तो (बालुरघाट)
35. कॉमरेड विकाश नोना (तपन)
36. कॉमरेड अमृत बर्मन (गंगारामपुर)
37. कॉमरेड ललित ओरांव (हरिरामपुर)

मालदह जिला
38. कॉमरेड विमल मुर्मू (हबीबपुर)
39. कॉमरेड सुपेन कुमार राय (गाजल)
40. कॉमरेड झन्टू कुमार रविदास (चांचल)
41. कॉमरेड मुशर्रफ हुसैन (हरिश्चंद्रपुर)
42. कॉमरेड गौतम सरकार (इंग्लिश बाजार)
43. कॉमरेड आनन्द घोष (वैष्णव नगर)
44. कॉमरेड बासुदेव सरकार (मालदह)

मुर्शिदाबाद जिला
45. कॉमरेड रबिउल हक (समशेरगंज)
46. कॉमरेड अनूप सिन्हा (सुती)
47. कॉमरेड मिर्जा नसीरुद्दीन (जंगीपुर)
48. कॉमरेड रबिउल आलम (रघुनाथगंज)
49. कॉमरेड मिर्जा लुत्फल हक (सागरदिघी)
50. कॉमरेड मुन्तसिर जमील (लालगोला)
51. कॉमरेड उमर खैयाम (भगवानगोला)
52. कॉमरेड श्यामल मंडल (रानीनगर)
53. कॉमरेड मिलिया सजेम (मुर्शिदाबाद)
54. कॉमरेड बरुन मंडल (नवग्राम)
55. कॉमरेड श्रीकांत दास (कांदी)
56. कॉमरेड बाबर अली (रेजीनगर)
57. कॉमरेड लुकमान हकीम (बेलडांगा)
58. कॉमरेड दिलीप दास (बहरमपुर)
59. कॉमरेड अबू सईद खान्दकार (हरिहरपाड़ा)
60. कॉमरेड अब्दुस सलाम (नवदा)
61. कॉमरेड ऐशा सिद्दीकी (डोमकल)
62. कॉमरेड एनामुल हक (जलंगी)

नदिया जिला
63. कॉमरेड धनपति मंडल (करीमपुर)
64. कॉमरेड नजमुल अंसारी (तेहट्ट)
65. कॉमरेड अनारुल हक (पलाशीपाड़ा)
66. कॉमरेड महिउद्दीन मंडल (कालीगंज)
67. कॉमरेड मशिकुर रहमान (नकाशीपाड़ा)
68. कॉमरेड मोजम्मेल हुसैन मंडल (चापड़ा)
69. कॉमरेड जयदीप चौधुरी (कृष्णनगर उत्तर)
70. कॉमरेड प्रबीर डे (कृष्णनगर दक्षिण)
71. कॉमरेड अपर्णा गुहा (रानाघाट उत्तर पश्चिम)
72. कॉमरेड असित बरण बिश्वास (कृष्णगंज)
73. कॉमरेड जगदीश मंडल (रानाघाट उत्तर पूर्व)
74. कॉमरेड ननी गोपाल मिस्त्री (रानाघाट दक्षिण)
75. कॉमरेड अर्चना भट्टाचार्य (चाकदह)
76. कॉमरेड प्राणकृष्ण बिश्वास (कल्याणी)
77. कॉमरेड विप्लब दास (हरिणघाटा)

उत्तर 24 परगना जिला
78. कॉमरेड स्वपन मंडल (बागदा)
79. कॉमरेड श्याम सुन्दर हालदार (बनगांव उत्तर)
80. कॉमरेड रवीन्द्रनाथ बारुई (बनगांव दक्षिण)
81. कॉमरेड शिवानी मजुमदार (गाईघाटा)
82. कॉमरेड प्रबोध सरकार (हाबड़ा)
83. कॉमरेड तारक दास (अशोकनगर)
84. कॉमरेड कमाल उद्दीन (आमडांगा)
85. कॉमरेड अभिजीत मुखर्जी (बारासात)
86. कॉमरेड सादेक मंडल (देगंगा)
87. कॉमरेड देवब्रत बिश्वास (स्वरूपनगर)
88. कॉमरेड निताई कृष्ण पाल (बादुरिया)
89. कॉमरेड हिरण्मय मंडल (बसिरहाट दक्षिण)
90. कॉमरेड अपर्णा बिश्वास (मध्यमग्राम)
91. कॉमरेड सीमा नंदी (बीजपुर)
92. कॉमरेड संजय राय (नैहाटी)
93. कॉमरेड सुजीत बोस (भाटपाड़ा)
94. कॉमरेड प्रणव चौधुरी (जगद्दल)
95. कॉमरेड चन्द्रशेखर चौधरी (पानीहाटी)
96. कॉमरेड अमल सेन (बैरकपुर)
97. कॉमरेड नीरेन कर्मकार (दमदम)
98. कॉमरेड सुनील नस्कर (राजारहाट न्यू टाउन)
99. कॉमरेड उमा पंडा (बिधाननगर)
100. कॉमरेड सुप्रिय भट्टाचार्य (बरानगर)
101. कॉमरेड सुबीर चौधुरी (राजारहाट गोपालपुर)

दक्षिण 24 परगना जिला
102. कॉमरेड हरिपद मंडल (गोसाबा)
103. कॉमरेड मिलन बिश्वास (बासंती)
104. कॉमरेड रामप्रसाद मिस्त्री (कैनिंग पश्चिम)
105. कॉमरेड रफीक आकुंजी(कैनिंग पूर्व)
106. कॉमरेड नारायण चन्द्र हालदार (पाथरप्रतिमा)
107. कॉमरेड झन्टू माइती (काकद्वीप)
108. कॉमरेड अनुपम पाणि (सागर)
109. कॉमरेड यमुना तांती (कुलपी)
110. कॉमरेड निरंजन नस्कर (जयनगर)
111. कॉमरेड जयदेव नस्कर (बारुईपुर पूर्व)
112. कॉमरेड प्रद्युत चक्रवर्ती रिन्टूदा (बारुईपुर पश्चिम)
113. कॉमरेड शंकर नस्कर (कुलतली)
114. कॉमरेड गुणसिन्धु हालदार (रायदिघी)
115. कॉमरेड शिशिर मंडल (मंदिरबाजार)
116. कॉमरेड सोमनाथ नस्कर (मगराहाट पूर्व)
117. कॉमरेड गोरा जमादार (मगराहाट पश्चिम)
118. कॉमरेड सम्पा सरकार (कसबा)
119. कॉमरेड प्रो. देवब्रत बेरा (जादवपुर)
120. कॉमरेड अनिन्द्या रायचौधुरी (सोनारपुर उत्तर)
121. मिनती मित्रा (सोनारपुर दक्षिण)
122. कॉमरेड सुमिता बनर्जी मुखर्जी (टालीगंज)
123. कॉमरेड आशीष सामंत (बेहाला पूर्व)
124. कॉमरेड संजय बिश्वास (बेहाला पश्चिम)
125. कॉमरेड संगीता भक्त (महेशतला)
126. कॉमरेड बासुदेव काबड़ी (बजबज)
127. कॉमरेड रीना राय (मेटियाबुर्ज)
128. कॉमरेड उत्तम पाल (सातगाछिया)

कोलकाता जिला
129. कॉमरेड श्रीचान्द बिन्द (कोलकाता पोर्ट)
130. कॉमरेड अनुमिता साव (पाणि) (भवानीपुर)
131. कॉमरेड दिलीप हालदार (रासबिहारी)
132. कॉमरेड आइसानुल हक (बालीगंज)
133. कॉमरेड प्रबीर शील (चौरंगी)
134. कॉमरेड डॉ. साम्स मुशाफिर (एन्टाली)
135. कॉमरेड जयंती मित्रा (बेलेघाटा)
136. कॉमरेड डॉ. अंशुमान मित्रा (जोड़ासाँको)
137. कॉमरेड प्रो. गौरांग खाटुआ (श्यामपुकुर)
138. कॉमरेड सुबीर सामंत (माणिकतला)
139. कॉमरेड डॉ नीलरतन नाईया (काशीपुर बेलगाछिया)

हावड़ा जिला
140. कॉमरेड पुतुल चौधुरी (बाली)
141. कॉमरेड श्रीरूप दास (हावड़ा मध्य)
142. कॉमरेड कार्तिक शील (शिवपुर)
143. कॉमरेड रीता घोषाल (हावड़ा दक्षिण)
144. कॉमरेड सुखेन मंडल (उलुबेड़िया पूर्व)
145. कॉमरेड जयंत खाटुआ (उलुबेड़िया दक्षिण)
146. कॉमरेड अलोक दलपति (श्यामपुर)
147. कॉमरेड विश्वनाथ बेरा (बागनान)
148. कॉमरेड संजीव सांतरा (आमता)

हुगली जिला
149. कॉमरेड तपन चौधुरी (उत्तरपाड़ा)
150. कॉमरेड समीर सरकार (श्रीरामपुर)
151. कॉमरेड सुकांत पोड़ेल (सिंगुर)
152. कॉमरेड सुखदेव बिश्वास (बालागढ़)
153. कॉमरेड श्यामली कुमार (पांडुआ)
154. कॉमरेड शिशिर राय (हरिपाल)
155. कॉमरेड कुमुद मंडल(चन्दननगर)

पूर्व मेदिनीपुर जिला
156. कॉमरेड अरुण जाना (तमलुक)
157. कॉमरेड आनन्द हांडा (पांसकुड़ा पूर्व)
158. कॉमरेड स्नेहलता साहू (पांसकुड़ा पश्चिम)
159. कॉमरेड जगदीश माइती (मैना)
160. कॉमरेड सौमित्र पट्टनायक (नन्दकुमार)
161. कॉमरेड तपन माइती (महिषादल)
162. कॉमरेड शुभेन्दु शेखर दास (हलदिया)
163. कॉमरेड विमल कुमार माइती (नंदीग्राम)
164. कॉमरेड रीता भौमिक (चंडीपुर)
165. कॉमरेड सुर्येंदु पात्रा (पटाशपुर)
166. कॉमरेड सुभाष पायरा (कांथी उत्तर)
167. कॉमरेड गोपाल पात्रा (भगवानपुर)
168. कॉमरेड पवित्र मंडल (खेजुरी)
169. कॉमरेड रफीकुल इस्लाम (कांथी दक्षिण)
170. कॉमरेड नारायण बर्मन (रामनगर)
171. कॉमरेड सनातन गिरी (एगरा)

झाड़ग्राम जिला
172. कॉमरेड कालीचरण बेसरा (नयाग्राम)
173. कॉमरेड धर्मपाल बिसुई (गोपीबल्लभपुर)
174. कॉमरेड सुभाष सिंह (झाड़ग्राम)
175. कॉमरेड राजीव मुदी (बिनपुर)

पश्चिम मेदिनीपुर जिला
176. कॉमरेड सुभाष दास (दांतन)
177. कॉमरेड सुनील सिंह (केशियाड़ी)
178. कॉमरेड श्यामापद जाना (नारायणगढ़)
179. कॉमरेड सुरंजन महापात्रा (खड़गपुर सदर)
180. कॉमरेड तपन शासमल (सबंग)
181. कॉमरेड शिशिर मान्ना (पिंगला)
182. कॉमरेड अक्षय खान (खड़गपुर)
183. कॉमरेड दीपांकर माइती (डेबरा)
184. कॉमरेड अंजन जाना (चन्द्रकोणा)
185. कॉमरेड तापस मिश्र (गढ़बेता)
186. कॉमरेड झरना जाना (शालबनी)
187. कॉमरेड हाराधन सिंह (केशपुर)
188. कॉमरेड सुश्रिता सोरेन (मेदिनीपुर)
189. कॉमरेड नाडूगोपाल दोलाई (घाटाल)
190. कॉमरेड जगदीश मंडल अधिकारी (दासपुर)

पुरुलिया जिला
191. कॉमरेड भोलानाथ मुर्मू (बलरामपुर)
192. कॉमरेड परितोष सिंह बाबू (बाघमुंडी)
193. कॉमरेड सुफल कुमार (जयपुर)
194. कॉमरेड शोभा माहातो (पुरुलिया)
195. कॉमरेड स्वपन मुर्मू (मानबाजार)
196. कॉमरेड दीपक माहातो (काशीपुर)
197. कॉमरेड जगन्नाथ बाउरी (पाड़ा)
198. कॉमरेड अनिल बाउरी (रघुनाथपुर)

बांकुड़ा जिला
199. कॉमरेड दीपेन बाउरी (शालतोड़ा)
200. कॉमरेड अविनाश हांसदा (छातना)
201. कॉमरेड रंजनलाल टुडू (रानीबांध)
202. कॉमरेड गुनाराम हांसदा (रायपुर, बांकुड़ा)
203. कॉमरेड शुभेन्दु माहातो (तालडांगरा)
204. कॉमरेड लीना घोष (बांकुड़ा)
205. कॉमरेड प्रदीप बाउरी (बड़जोड़ा)
206. कॉमरेड मागाराम घोष (ओन्दा)
207. कॉमरेड शशिभूषण बनर्जी (विष्णुपुर)
208. कॉमरेड मोहन सांतरा (कोतुलपुर)
209. कॉमरेड दिलीप कुमार साहा (सोनामुखी)

पूर्व बर्द्धमान जिला
210. कॉमरेड उत्पल दत्ता (बर्द्धमान दक्षिण)
211. कॉमरेड अतसी पाकड़े (जमालपुर)
212. कॉमरेड नीलरतन बिश्वास (कालना)
213. कॉमरेड अपूर्व चक्रवर्ती (काटोआ)
214. कॉमरेड सत्यनारायण मंडल (केतुग्राम)
215. कॉमरेड रसिक सोरेन (मंगलकोट)
216. कॉमरेड मनसा मेटे (आउशग्राम)
217. कॉमरेड प्रभात माझी(पूर्वस्थली दक्षिण)

पश्चिम बर्द्धमान जिला
218. कॉमरेड दना गोस्वामी (पांडूबेश्वर)
219. कॉमरेड किरणमयी मंडल (दुर्गापुर पूर्व)
220. कॉमरेड सोमनाथ बनर्जी (दुर्गापुर पश्चिम)
221. कॉमरेड अनूप भट्टाचार्य (आसनसोल दक्षिण)
222. कॉमरेड कल्लोल राय (आसनसोल उत्तर)
223. कॉमरेड देबसर बेसरा (बाराबनी)

बीरभूम जिला
224. कॉमरेड निताई अंकुर (सिउड़ी)
225. कॉमरेड समरजीत बर्मन (बोलपुर)
226. कॉमरेड नव कुमार दास (साईंथिया)
227. कॉमरेड फरीदा याश्मीन (रामपुरहाट)
228. कॉमरेड सुबर्ण माल (हासन)
229. कॉमरेड मार्शल हेम्ब्रम (नलहाटी)
230. कॉमरेड बन्छाराम माल (मुरारई)

असम में 42 विधानसभा सीटों से लड़ रही एसयूसीआई (कम्युनिस्ट)

असम विधानसभा चुनाव में 42 सीटों पर लड़ रही एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की राज्य सचिव कॉमरेड चंद्रलेखा दास ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि असम विधानसभा का चुनाव ऐसे समय में होने जा रहा है, जब पूरा राज्य चौतरफा संकट–आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक–से जूझ रहा है। तमाम आवश्यक वस्तुओं की बेतहाशा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के अभूतपूर्व संकट ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। नतीजतन, राज्य की आम जनता ने भाजपा–नीत एनडीए और कांग्रेस–नीत विपक्षी गठबंधन द्वारा चलाये जा रहे अभियानों में बहुत कम रुचि दिखायी है। ऐसा इसलिए कि आम लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि चाहे कोई भी गठबंधन चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाये, वह उन्हें उन गंभीर समस्याओं से कोई राहत नहीं दिलायेगा, जिनसे वे जूझ रहे हैं।

हमारी पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) का यह दृढ़ मत है कि केवल जनवादी आन्दोलनों के जरिये ही जनता की कुछ जायज मांगें हासिल की सकती हैं।

इसलिए समय की मांग है कि पूंजीपति वर्ग के धन बल और प्रचार के बल पर पलने वाले भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले दोनों गठबंधनों को चुनाव में परास्त किया जाये और राज्य में वास्तविक वाम–जनवादी आन्दोलन को पुनर्जीवित किया जाये। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने राज्य के बयालीस (42) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है।

हम राज्य की जनता से एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवारों विजयी बनाने की पुरजोर अपील करते हैं।

2026 के असम विधानसभा चुनाव में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) प्रत्याशियों की सूची

गोआलपाड़ा जिला
1. गोआलपाड़ा (पश्चिम) – कॉमरेड मृत्युंजय राभा
2. गोआलपाड़ा (पूर्व) – कॉमरेड मोहिबुल इस्लाम
3. जलेश्वर – कॉमरेड सैफुल इस्लाम

धुबरी जिला
4. धुबरी – कॉमरेड साहाना अख्तर
5. बीरसिंह–जरुआ – कॉमरेड अब्दुस सोबुर मिया

दक्षिण सालमारा–मानकाचर जिला
6. मानकाचर – कॉमरेड सहिदुर आलम

बोंगाईगांव जिला
7. बोंगाई गांव – कॉमरेड प्रणीता बर्मन
8. सृजनग्राम – कॉमरेड हनीफ अली शेख

बरपेटा जिला
9. चेंगा – कॉमरेड जहिरुल इस्लाम
10. पाका बेतबाड़ी – कॉमरेड हालिमा खातून

नलबाड़ी जिला
11. नलबाड़ी – कॉमरेड केनेडी पेगु
12. बरखेत्री – कॉमरेड मुनीन्द्र डोले
13. तिहू – कॉमरेड प्रमोद भगवती

कामरूप (ग्राम्य) जिला
14. कमालपुर – कॉमरेड शिशिर काकती
15. समरिया – कॉमरेड दिलवारा हुसैन

तामुलपुर जिला
16. गोरेश्वर – कॉमरेड कबिन बोड़ो

दर्रांग जिला
17. मंगलदई – कॉमरेड अजीत आचार्य
18. सिपाझार – कॉमरेड मुन डेका

उड़ालगुड़ी जिला
19. टंगला – कॉमरेड जितेन्द्र चलिहा
20. भेरगांव – कॉमरेड स्वर्णलता चलिहा

सोनितपुर जिला
21. तेजपुर – कॉमरेड नयनमणि चौधरी
22. बरछला – कॉमरेड चंपा कुर्मी

लखीमपुर जिला
23. लखीमपुर – कॉमरेड बिरिंची पेगु
24. रंगानदी – कॉमरेड हेमकांत मिरी
25. ढकुआखाना – कॉमरेड जूतिका डोले

धेमाजी जिला
26. धेमाजी – कॉमरेड लिली डोले

डिब्रूगढ़ जिला
27. नाहरकटिया – कॉमरेड महेन्द्र धडुमिया

जोरहाट जिला
28. जोरहाट – कॉमरेड हेमंत पेगु

माजुली जिला
29. माजुली – कॉमरेड भाईटी रिचांग

नगांव जिला
30. नगांव बटाद्रवा – कॉमरेड वर्णाली शर्मा

कछार जिला
31. सिलचर – कॉमरेड भवतोष चक्रवर्ती
32. धलाई – कॉमरेड गौरचन्द्र दास
33. उदारबंद – कॉमरेड दिलीप री
34. बरखोला – कॉमरेड चंपा डे
35. सोनाइ – कॉमरेड अंजन कुमार चंद
36. काटीगाड़ा – कॉमरेड हिल्लोल भट्टाचार्य

करीमगंज जिला
37. करीमगंज (उत्तर) – कॉमरेड अरुणांशु भट्टाचार्य
38. करीमगंज (दक्षिण) – कॉमरेड रूपश्री गोस्वामी
39. रामकृष्ण नगर – कॉमरेड संचिता शुक्ला
40. पाथरकांडी – कॉमरेड विजित कुमार सिन्हा

हैलाकांदी जिला
41. हैलाकांदी – कॉमरेड मयूख भट्टाचार्य
42. आलगापुर – कॉमरेड अल्ताफ हुसैन मजुमदार

केरल विधानसभा चुनाव : 32 सीटों से लड़ रही एसयूसीआई (कम्युनिस्ट)

केरल विधानसभा चुनाव में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने 32 सीटों से अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। तिरुवनंतपुरम से लेकर कन्नूर तक, 14 में से 13 जिलों में पार्टी के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी ने ऐसे व्यक्तियों को अपने उम्मीदवार के रूप में चुना है, जो जन आन्दोलनों की अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व करते रहे हैं।

इस संबंध में 18 मार्च को तिरुवनंतपुरम में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉमरेड जैसन जोसेफ ने कहा : "कॉर्पोरेट नीतियों को लागू करके आम लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाले मोर्चों को खारिज करें और जन आन्दोलनों की निर्विवाद शक्ति, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवारों को विजयी बनायें। सत्ता में आने वाले सभी मोर्चे कॉर्पोरेट के हित साधते हैं, जिससे लोगों की दुख–तकलीफें बढ़ती हैं। महंगाई, बेरोजगारी और शुल्कों व करों में वृद्धि लोगों के लिए असहनीय हो गयी है। सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार, नशीले पदार्थों का प्रसार, महिलाओं के प्रति जुल्म–अत्याचार और माफियाओं की क्रूरता फल–फूल रही है। लोगों के विरोध को दबाया जा रहा है। जनता की एकता को तोड़ने के लिए साम्प्रदायिकता की आग भड़काई जा रही है।

केन्द्र की मोदी सरकार के मजदूर–विरोधी श्रम कोडों से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक, जो आम लोगों को वास्तविक शिक्षा से वंचित करती है और ज्ञान का व्यापारीकरण व सांप्रदायीकरण करती है–पिनाराई सरकार केरल में वामपंथ के नाम पर भाजपा की उन्हीं नीतियों को लागू कर रही है। यह वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार केन्द्र सरकार की कॉर्पोरेट–समर्थक नीति 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार करने में सुगमता) का ही अनुसरण कर रही है। इस बीच, केन्द्र और राज्य सरकारें सच्चाई को छिपाने के लिए सार्वजनिक खजाने से करोड़ों रुपये खर्च करके पीआर एजेंसियों के जरिये झूठा प्रचार फैलाने में होड़ कर रही हैं। इसलिए हमारा मानना है कि जनता का मुख्य कार्यभार इन सभी कॉर्पोरेट परस्त मोर्चों को परास्त करना है।

ऐसी स्थिति में, जन–हितैषी नीतियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नाइंसाफी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष और जन आन्दोलनों को मजबूत किया जाना चाहिए। विधानसभा में जन आन्दोलनों के नेताओं को चुनकर ऐसी स्थिति बनायी जानी चाहिए, जिससे कि जनता की आवाज को अनसुना और नजरअंदाज न किया जा सके। बुनियादी सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक सच्ची वामपंथी राजनीति के विकास को सुनिश्चित करने का भी यही रास्ता है।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) एक ऐसी पार्टी है, जिसने पिछले छह दशकों से राज्य में इस राजनीति को कायम रखा है और कई जन आन्दोलनों को जीत तक पहुंचाया है। पार्टी के उम्मीदवार वे लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन से साबित किया है कि वे दृढ़तापूर्वक जनता के साथ खड़े हैं। हमें उम्मीद है कि मतदाता उनकी जीत सुनिश्चित करने के कार्य को अपना कर्तव्य समझेंगे।"

2026 के केरल विधानसभा चुनाव में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) प्रत्याशियों की सूची

कन्नूर जिला
1. अझिकोड – कॉमरेड रश्मि रवि
2. कन्नूर – कॉमरेड एम.के. शहजाद

वायनाड जिला
3. सुल्तान बाथरी (एसटी) – वी.ए. रमेश

कोझिकोड जिला
4. एलाथुर – कॉमरेड पी.एम. श्रीकुमार
5. कोझिकोड उत्तर – कॉमरेड ए. सजीना

मलप्पुरम जिला
6. तिरूर – कॉमरेड डॉ. एस. अलीना

पलक्कड़ जिला
7. मालमपुझा – कॉमरेड के. प्रसाद

त्रिशूर जिला
8. गुरुवायूर – कॉमरेड सी.आर. उन्नीकृष्णन
9. कोडुंगल्लूर – कॉमरेड नंदगोपन एम.एन.

एर्नाकुलम जिला
10. अंगमाली – कॉमरेड पी. वी. राजेश
11. कलमस्सेरी – कॉमरेड रजीना ए.
12. त्रिपुनिथुरा – कॉमरेड के.ए. सतीशन
13. पिरावोम – कॉमरेड टी.सी. रामनन

इडुक्की जिला
14. थोडुपुझा – कॉमरेड पी.टी. वर्गीज

कोट्टायम जिला
15. वैकोम – कॉमरेड टी.एम. बोस
16. एट्टुमनूर – कॉमरेड आशना थम्बी
17. कोट्टायम – कॉमरेड रालेश चन्द्रन
18. चंगनास्सेरी – कॉमरेड अरविन्द वी.
19. पूंजर – कॉमरेड मायामोल के.पी.

अलाप्पुझा जिला
20. अरूर – कॉमरेड के.पी. मनोहरन
21. अंबालापुझा – कॉमरेड जॉनसन मैथ्यू
22. कुट्टनाड – कॉमरेड पी.के. शशि
23. हरिपद – कॉमरेड विद्या वी.पी.
24. चेंगन्नूर – कॉमरेड प्रनीश बी.

पतनमतिट्टा जिला
25. अरनमुला – कॉमरेड एस. राधामणि

कोल्लम जिला
26.करुनागप्पल्ली– कॉमरेड ट्विंकल प्रभाकरन
27. कुन्नाथूर – कॉमरेड टी. शशिधरन
28. पुनालूर – कॉमरेड आर. महेश
29. कुंडारा – राहुल आर.

तिरुवनंतपुरम जिला
30. वट्टीयोरकावु – कॉमरेड एमिल बी.एस.
31. तिरुवनंतपुरम – कॉमरेड ए. सबूरा
32. नेमोम – कॉमरेड करमना प्रसाद

तमिलनाडु में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवारों को विजयी बनायें

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) तमिलनाडु राज्य कमेटी ने 18 मार्च को जारी प्रेस बयान में कहा:

"17वें विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। सत्ता में आने से पहले जनता से किये गये अपने वादों को पूरा करने में विफल रही तमिलनाडु की मौजूदा सत्ताधारी जनविरोधी डीएमके गठबंधन सरकार सत्ता बरकरार रखने को लालायित है। साथ ही, एआईएडीएमके गठबंधन, जो अपने भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है और जिसने एकाधिकारवादी कॉर्पोरेट–समर्थित साम्प्रदायिक भाजपा से गठजोड़ किया है, फिर से सत्ता में आने की फिराक में है। पूंजीपतियों द्वारा पेश की गयी दो नयी पार्टियां, यानी नाम तमिलर काची (एनटीके), जो तमिल राष्ट्रवादी अंध–देशभक्ति की बात करती है और तमिलर वेत्री कलगम (टीवीके), जो युवा मतदाताओं के एक तबके को भ्रमित करने के लिए एक लोकप्रिय फिल्म स्टार की छवि का निवेश के रूप में उपयोग करती है, डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधनों के प्रति जनता के आक्रोश का लाभ उठाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं।

इनमें से किसी भी पार्टी ने उदारीकरण व निजीकरण की नीति को छोड़ने का वादा नहीं किया है, जो कि बुनियादी समस्याओं का कारण है और न ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद और वितरण पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने और उन्हें जनता को कम कीमतों पर वितरित करने का वादा किया है। इसके बजाय, उन्होंने एक बार फिर केवल आकर्षक रेवड़ियां बांटने का वादा किया है।

एसयूसीआई (कम्युस्ट) पार्टी केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा लायी गयी नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020), जो शिक्षा का पूरी तरह

(शेष पृष्ठ 8 पर)

एआईयूटीयूसी का बयान

लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

आंगनबाड़ी कर्मियों के आंदोलन को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ एआईयूटीयूसी के उत्तर प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड वालेन्द्र कटियार ने 7 मार्च को जारी बयान में कहा:

"प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मी लम्बे अर्से से अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखती आ रही हैं, लेकिन सरकार उनकी जायज मांगों को मान नहीं रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय के नाम पर सबसे कम पैसा उत्तर प्रदेश में ही दिया जा रहा है। 8 मार्च को जब वे अपनी बात कहने के लिए लखनऊ जा रही हैं, तो उनके नेताओं को उनके ही घरों पर नजरबंद कर आंदोलन को रोकने की सरकार की कार्रवाई न सिर्फ निन्दनीय है, बल्कि एक जनतांत्रिक देश में जनता के जनवादी अधिकारों का हनन का प्रयास भी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कर्मियों के नेताओं को तुरंत रिहा करे और उनकी जायज मांगों को अविलंब पूरा करे।"

गिग वर्कर्स यूनियन गठित

भोपाल, मध्य प्रदेश। 12 मार्च को ऐप आधारित गिग वर्कर्स और बाइक टैक्सी ऑपरेटरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य वक्ता कॉमरेड शांति घोष थे। जल्द से जल्द एक राज्य स्तरीय संघ पंजीकृत कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। संघ का नाम ऐप आधारित गिग वर्कर्स एंड बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन होगा।

सड़कों पर उतरीं एनएलआरएम वर्कर

कांकेर, छत्तीसगढ़। एआईयूटीयूसी से संबद्ध एनआरएलएम सक्रिय महिला संघ व कृषि सखी पशु सखी संघ छत्तीसगढ़ की ओर से 19 फरवरी से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल और 16 मार्च से जिला कांकेर में लगातार धरना-प्रदर्शन जारी है। 17 मार्च को कांकेर जिला में विशाल रैली आयोजित की गई और ज्ञापन सौंपा गया।

इस वर्ष 5 जनवरी व 15 जनवरी को रायपुर में प्रदर्शन किया गया। पंचायत मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलकर ज्ञापन दिया गया व वार्ता की गई। शासन-प्रशासन के उदासीन रवैये के खिलाफ 19 फरवरी रायपुर में फिर से प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन इस प्रदर्शन के प्रति पुलिस का रवैया दमनात्मक रहा। उसके बाद 24 फरवरी के बजट में लखपति दीदी का प्रचार-प्रसार तो किया गया, किंतु एनआरएलएम कैडर महिलाएं, जो लखपति दीदी बनाती हैं, उनकी मांगों की पूर्ति संबंधी कोई घोषणा नहीं की गई। अत: आंदोलन जारी है। एनआरएलएम की हजारों महिला कैडर निर्भीकता से आंदोलन के मैदान में डटी हुई हैं।

शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर जगह-जगह कार्यक्रम

नई दिल्ली।

23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगत सिंह राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर शहीद पार्क में मजदूरों ने 'पूंजीवाद-साम्राज्यवाद मुर्दाबाद' का नारा लगाते हुए शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

पटना, बिहार।

आजादी आंदोलन की गैरसमझौतावादी धारा के महान योद्धाओं शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव का शहादत दिवस एआईडीएसओ की ओर से स्थानीय गांधी मैदान स्थित भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष, पटना कॉलेज परिसर और सर जी.डी. पाटलिपुत्र स्कूल में मनाया गया।

रोहतक, हरियाणा।

शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर यहां भरत कॉलोनी में बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम कॉमरेड हरीश कुमार सैनी के नेतृत्व में एआईडीवाईओ द्वारा संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए निबंध लेखन, भाषण एवं देशभक्ति कविताओं की शानदार प्रस्तुतियां दीं। इस मौके पर अभिभावकों ने भी सक्रिय भागीदारी की तथा क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को और अधिक जीवंत एवं भावनात्मक बना दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

कॉमरेड हरीश कुमार सैनी ने सभी नागरिकों, खासकर युवाओं से हर तरह के शोषण-जुल्म के खिलाफ आगे आने और एक न्यायपूर्ण, समतामूलक एवं प्रगतिशील समाज बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

इसके अलावा, एमडीयू में एआईडीएसओ ने स्मृति सभा कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

हांसी, हरियाणा।

आजादी आंदोलन की समझौतहीन संघर्ष की धारा के प्रतिनिधि शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का 95वां शहादत दिवस स्थानीय टैक्सी स्टैंड स्थित यूनियन कार्यालय में एआईयूटीयूसी व एआईकेकेएमएस की ओर से साम्राज्यवाद-विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी के जिला प्रधान कॉमरेड सत्यनारायण भाटोल व किसान संगठन एआईकेकेएमएस के जिला सचिव कॉमरेड हवा सिंह संघर्ष ने संयुक्त रूप से की व संचालन कॉमरेड विजेंद्र जीतपुरा ने किया।

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एआईयूटीयूसी के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला सचिव मेहर सिंह बांगड़ ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियनों के सांझा मंच के आह्वान पर आज का दिन सारे देश में अमरीका व इजरायल द्वारा ईरान पर किये जा रहे बर्बर हमलों के विरोध में साम्राज्यवाद-विरोधी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कॉमरेड बांगड़ ने इन हमलों की कड़ी निन्दा करते हुए इस युद्ध के खिलाफ दुनिया के शांतिकामी लोगों को एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का आह्वान किया।

शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हों ने कहा कि शहीदों का शोषणहीन समाज बनाने का सपना आज भी अधूरा है। भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति से हमारा अभिप्राय मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। लेकिन देश की आजादी के 78 साल बाद भी देश की जनता आज महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी व भुखमरी की मार झेलने पर मजबूर है। भगत सिंह सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे।

जमशेदपुर, झारखंड।

23 मार्च को छात्र संगठन एआईडीएसओ, युवा संगठन एआईडीवाईओ और महिला संगठन एआईएमएसएस की ओर से शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का 95वां शहादत दिवस साकची गोलचक्कर पर मर्यादापूर्वक मनाया गया। छात्र-छात्राओं द्वारा क्रांतिकारी गीतों की प्रस्तुति दी गई।

कार्यक्रम का संचालन एआईडीएसओ की जमशेदपुर नगर अध्यक्ष कॉमरेड सविता सोरेन ने किया। धन्यवाद ज्ञापन नगर सचिव कॉमरेड खुदीराम हसदा ने दिया।

देश में धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक व जनवादी शिक्षा कायम करने के लिए संघर्ष तेज करने पर बल दिया।

सम्मेलन को एआईडीएसओ के पूर्व उपाध्यक्ष कॉमरेड मुकेश सेमवाल, एआईडीएसओ, केंद्रीय परिषद के कार्यालय सचिव कॉमरेड प्रशांत कुमार और एआईडीएसओ, केंद्रीय परिषद की संयुक्त सचिव कॉमरेड श्रुति शिवहरे ने संबोधित किया। अंत में कुलदीप चंद को अध्यक्ष, मोनिका चौहान को उपाध्यक्ष, रंजना बर्तवाल को सचिव, अजय को कोषाध्यक्ष व हिमानी को कार्यालय सचिव सहित 21 सदस्यीय पहली उत्तराखंड राज्य परिषद चुनी गयी।

घाटशिला

नारनौल

मुजफ्फरपुर

जमशेदपुर

सभा को शिक्षक अजय मेहताब, एआईडीएसओ के प्रदेश सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड प्रदीप कुमार यादव, एआईएमएसएस की जिला सचिव कॉमरेड शीला रॉय और एआईडीवाईओ जिला सचिव कॉमरेड राजीव दास ने संबोधित किया।

देहरादून, उत्तराखंड।

23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के शहादत दिवस पर एआईडीएसओ उत्तराखंड का पहला छात्र सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन ने एआईडीएसओ संपर्कों और उत्तराखंड के कई बुद्धिजीवियों के बीच भी बहुत उत्साह पैदा किया। एनईपी-2020 के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने, पर्यावरण बचाओ और अन्य जनमुद्दों को लेकर एआईडीएसओ के प्रयास की प्रसिद्ध पर्यावरणविद् रवि चोपड़ा, कुमाऊं में शिक्षा विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक शिव प्रसाद सेमवाल और वरिष्ठ पत्रकार एसएमए काजमी जैसे वक्ताओं ने काफी सराहना की।

वक्ताओं ने हमारे महान शहीदों के विचार जन-जन तक ले जाने और

बडोदरा

अहमदाबाद

पटना

बिजली(संशोधन) विधेयक-2025 का विरोध

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 10 मार्च को राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के क्रम में उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ता संगठन, जिला मुरादाबाद ने यहां जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री को श्रीमान जिलाधिकारी मुरादाबाद की मार्फत भेजे ज्ञापन में बिजली (संशोधन) विधेयक-2025 को वापस लेने की मांग की।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया

मयूर विहार, दिल्ली

दिल्ली : मयूर विहार कोंडली में शहीद व मनीषी यादगार मंच की तरफ से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं व आम लोगों ने हिस्सा लिया। सभा की अध्यक्षता एआईएमएसएस की दिल्ली राज्य सचिवमंडल सदस्य श्रीमती बासमती ने की, संचालन कॉमरेड नवीन राम ने किया और मुख्य वक्ता कॉमरेड हरीश त्यागी थे। उनके अलावा, कॉमरेड नीरज कुमार, कॉमरेड प्रभास, डॉक्टर अरना व अन्यों ने भी अपनी बातें रखीं।

ढकवा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।

महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) के तत्वावधान में 8 मार्च को यहां डॉ. भीमराव अम्बेडकर शिक्षण संस्थान में महिलाओं की एक सभा आयोजित की गई। इसकी शुरुआत में 'नारी जाग जरा', 'जो कर न सके औरत का सम्मान', 'बेखौफ आजाद होके जीना मुझे', 'कोमल है, कमजोर नहीं' जैसे महत्वपूर्ण गाने गाये गये।

मुख्य वक्ता संगठन की अखिल भारतीय कार्यालय सचिव कॉमरेड महुआ नंदा थीं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसयूसीआई (सी), पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड रविशंकर मौर्य के अलावा पूनम प्रजापति और अपर्णा शुक्ला ने सभा को सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता संगठन की ऑल इण्डिया कौंसिल सदस्य श्रीमती वंदना सिंह ने की और संचालन- अंजली सरोज ने किया।

इस अवसर पर सैकड़ों महिलाएं व छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का अंत 'हम होंगे कामयाब' गीत से हुआ।

ढकवा: सभा को सम्बोधित करती हुई कॉमरेड महुआ नंदा

शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खां व रोशन सिंह की मूर्तियां तोड़ने के खिलाफ

एआईडीवाईओ ने किया विरोध प्रदर्शन

बदलापुर, जौनपुर

मुजफ्फरपुर

बदलापुर, जौनपुर, उ.प्र।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नगर निगम परिसर में स्थापित आजादी आंदोलन के महान क्रांतिकारियों व काकोरी ऐक्शन के अमर शहीदों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान व रोशन सिंह की प्रतिमाओं को रात के 3 बजे नगर निगम प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया और अपमानित तरीके से कूड़ेदान में डाल दिया गया, जो बेहद निन्दनीय व आपराधिक कृत्य है। इस घटना से पूरे प्रदेशभर के आजादी पसंद लोगों में रोष व्याप्त है।

उक्त घटना के खिलाफ काकोरी ऐक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति, जौनपुर की तरफ से 24 मार्च को बदलापुर के इंदिरा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जौनपुर रोड स्थित सब्जी मंडी से एक जोरदार जुलूस भी निकाला गया। जुलूस में काफी छात्र-नौजवान व महिलाएं शामिल हुए। सभी ने जोरदार नारे लगाते हुए मांग किया कि- शाहजहांपुर नगर निगम परिसर में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह की प्रतिमाओं को पुनः स्थापित किया जाए और उनकी मूर्तियों को तोड़ने वाले दोषियों को उदाहरणमूलक सजा दी जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के जौनपुर जिला सचिव प्रमोद कुमार शुक्ल ने की और संचालन जिला उपाध्यक्ष दिलीप कुमार खरवार ने किया। इन्दुकुमार शुक्ल, मिथिलेश कुमार मौर्य, संतोष कुमार प्रजापति, अंजली सरोज व अपर्णा शुक्ला ने कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

मुजफ्फरपुर, बिहार।

शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खां और रोशन सिंह की मूर्तियों को भाजपा सरकार द्वारा तोड़ने के आपराधिक कृत्य के खिलाफ एआईडीवाईओ ने 27 मार्च को यहां के कंपनी बाग में शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर एक सभा की।

विरोध प्रदर्शन को एआईडीवाईओ के अखिल भारतीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अरविंद कुमार ने सरकार से मांग की कि इस कृत्य में संलिप्त लोगों को तत्काल दंडित किया जाए और शहीदों की मूर्तियों को सम्मानपूर्वक वहीं पर पुनः लगाया जाए (जो बाद में लगा दी गईं)।

सभा को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र जिला इंचार्ज कॉमरेड अमन कुमार झा, जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड आशुतोष कुमार तथा एआईडीवाईओ के जिला सचिव कॉमरेड अनिल कुमार ने संबोधित किया। अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष कॉमरेड रंजीत कुमार ने की।

एआईएमएसएस का सफल महिला सम्मेलन आयोजित

हुसैनीवाला : सम्मेलन को सम्बोधित करती हुई कॉमरेड केया डे

हुसैनीवाला, फिरोजपुर, पंजाब।

ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) ने 22 मार्च को फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला के पास गांव गट्टी राजोंके में एक प्रेरणादायक महिला सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने जोशोखरोश के साथ हिस्सा लिया और जोशीले माहौल में जरूरी चर्चाएं हुईं।

सम्मेलन की शुरुआत में कॉमरेड सुनीता द्वारा पेश महिलाओं पर बढ़ते अपराध और पंजाब में ड्रग्स की बढ़ती समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जुझारू आंदोलन की जरूरत पर बल देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

सम्मेलन की मुख्य वक्ता थीं एआईएमएसएस की अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड केया डे। सम्मेलन को अखिल भारतीय सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड रितु कौशिक, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड सीता सिंह, कॉमरेड आशा रानी और कॉमरेड सुमन ने सम्बोधित किया।

सम्मेलन की अध्यक्षता मैडम बलवीर कौर रायकोटी संयोजक, एआईएमएसएस, पंजाब ने की और संचालन कॉमरेड पूजा रानी ने किया।

वक्ताओं ने महिलाओं से अपने परिवार, गांव और समाज को अपराधमुक्त बनाने, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने, युवाओं को इस सामाजिक बुराई का शिकार होने से बचाने के लिए के लिए आगे आने और आंदोलन गठित करने और शिक्षा के निजीकरण, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ चल रहे आंदोलन में बढ़-चढ़कर कर हिस्सा लेने की अपील की।

सम्मेलन के अन्त में एक 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कॉमरेड सरबजीत कौर को अध्यक्ष और कॉमरेड पूजा रानी को सचिव चुना गया।

एपस्टीन फाइल्स...

(पृष्ठ 1 का शेष)

और यौन व्यापार को बढ़ावा देने के आरोपों की औपचारिक तहकीकात करनी शुरू की। जांचकर्ताओं ने एक पैटर्न का पता लगाया: नाबालिग लड़कियों को नकद भुगतान के बदले एपस्टीन के ग्राहकों की "मालिश" करने के लिए भर्ती किया जाता था (ग्राहकों के नाम गुप्त रखने के लिए) और दूसरी लड़कियों की भर्ती करने की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। यह शोषण पिरामिड योजना की तरह संरचित था।

एपस्टीन की गतिविधियों की जांच

2007 तक अमेरिकी संघीय अभियोजकों के पास पर्याप्त सबूत थे। फिर भी उसके खिलाफ पूर्ण आरोप-पत्र दायर होना तो दूर रहा, एपस्टीन तत्कालीन अमेरिकी अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकॉस्टा के तहत एक गैर-अभियोजन समझौते (एनपीए) हासिल करने में सफल हुआ। उसने राज्य स्तर पर लगे आरोपों के लिए अपना अपराध कबूल किया और कार्य छूट के व्यापक विशेषाधिकारों सहित 13 महीने एक काउंटी सुविधा में बिताये। इसके बाद उस पर लगाये गए आरोप हटा दिये गए और किसी को भी इस तरह की माफी देने की शर्तों की जानकारी नहीं दी गई। कानूनी रूप से यह एक घोटाला था। बाद में अदालतों ने माना कि तस्करी करके लायी गई जिंदा बची लड़कियों के अधिकारों का हनन हुआ था। राजनीतिक रूप से यह आंखें खोलने वाला था। एनपीए ने प्रदर्शित किया कि तोड़े-मरोड़े हुए कानूनी प्रतिनिधित्व के साथ मिलकर अभियोगात्मक विवेकाधिकार कैसे आपराधिक कानून को एक बातचीत योग्य जरिये में बदल सकता है।

2018 में एक खोजी पत्रकार ने लगभग 80 कथित पीड़िताओं (ज्यादातर नाबालिग कमसिन उम्र की लड़कियों) की पहचान की, जिनका एपस्टीन या उसके सहयोगियों ने यौन शोषण किया था। इस रिपोर्ट के कारण एपस्टीन के खिलाफ यौन अपराध के आरोपों की फिर से जांच शुरू हुई।

2019 में उसके खिलाफ एक नया संघीय आपराधिक मामला दर्ज हुआ। जुलाई में उसे यौन देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन उस पर मुकदमा शुरू होने से पहले ही 10 अगस्त 2019 की सुबह उसे मैनहट्टन की जेल की कोठरी में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। यह आत्महत्या थी या हत्या यह अभी भी अस्पष्ट है।

जारी की गई एपस्टीन फाइलें

कथित तौर पर कुछ निहित स्वार्थी हलकों की ओर से इन एपस्टीन फाइलों को जारी करने से रोकने और उनमें से "प्रमुख" नामों को हटाने के उद्देश्य से दस्तावेजों में हेराफेरी करने की काशिश की गयी। अंत में, बहुत टालमटोल के बाद, खासकर जब पूरे 2025 में एपस्टीन के यौन शोषण से बच निकली लड़कियों और युवतियों (जिनकी संख्या अनुमानत: 1,000 से अधिक थी) की ओर से लगातार अपीलें की गईं, तब जाकर ये फाइलें सार्वजनिक की गईं।

'एपस्टीन फाइलों' में वर्षों से संचित जांच रिकॉर्ड शामिल हैं: गवाहियां, दूरसंचार से हुई बातें, तस्वीरें, वित्तीय दस्तावेज। इनका आंशिक तौर पर खुलासा जनता के जोरदार दबाव और कानूनी कार्रवाई के बाद हुआ। लेकिन यह खुलासा स्वयं एक राजनीतिक मामला बन गया। फाइलों में काट-छांटकर कुछ नामों को छिपाया गया। बची हुई लड़कियों की निजता भंग होने की चिंता जतायी गयी। यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या फाइलों की सभी सामग्री जारी भी की गई है या नहीं।

दूसरे शब्दों में, पूरी पारदर्शिता नहीं बरती गई। संस्थागत हिसाब-किताब से बीच-बचाव किया गया। यह तर्क दिया गया कि एपस्टीन से महज जुड़े होना अपराध की श्रेणी में नहीं है और दस्तावेजों में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक आचरण का आरोपी नहीं है। फिर भी 'शीर्ष स्तर' के लोगों के अंतर्संबंधों की अत्यधिक मौजूदगी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कई बुर्जुआ राजनीतिक नेता, राजघराने के लोग, बड़े उद्योगपति, शिक्षाविद-सभी एक ऐसे सामाजिक घेरे में दिखते हैं, जिसमें एक दोषी यौन अपराधी से उनका जुड़ाव सामान्य और स्पष्ट नजर आता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि मानव तस्करी करके लायी गई लड़कियों का इस्तेमाल एपस्टीन से जुड़े ऊंचे तबके के लोगों का "मनोरंजन" करने के लिए किया जाता था। इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प, एलन मस्क और अन्य बड़े नामों के साथ-साथ दुनियाभर के विभिन्न देशों के कई प्रमुख राजनेता और मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। जेफरी एपस्टीन के दस्तावेजों के ताजा खुलासे में ऐसे सबूत भी शामिल हैं, जिनसे दुनिया के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आने की संभावना है, जिससे दुनियाभर में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। अभी तक सिर्फ ब्रिटिश पूर्व सोशलाइट

(शेष पृष्ठ 8 पर)

PRGI Regn. No. 43022

भारतीय रेल :...

(पृष्ठ 1 का शेष)

11,000 से 11,500 से अधिक मालगाड़ियां चलाती है, जो देशभर के 7,000 से अधिक स्टेशनों को जोड़ती है। प्रतिदिन लगभग 2.3 से 2.5 करोड़ यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं। इसके अलावा, 68,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले विशाल मार्ग के जरिये भारतीय रेलवे सालाना 160 करोड़ टन से अधिक माल का परिवहन करती है। पूरे रेलवे सिस्टम में लगभग 1,300 माल गोदाम चालू हैं। लगभग 3,00,000 लोडिंग श्रमिक अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) के आधार पर कार्यरत हैं।

यह सर्वविदित है कि इतना बड़ा परिचालन नेटवर्क केवल भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के निवेश और वर्षों से लाखों रेल कर्मचारियों द्वारा किये गए कठिन परिश्रम से ही वास्तविकता बन सका है। वर्षों से लगभग 60 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति बनाने के लिए भारतीय जनता के पैसे का उपयोग किया गया है।

वास्तव में, स्वतंत्रता के ठीक बाद, जब देश का औद्योगिकीकरण अभियान पूंजीवादी पथ पर शुरू किया गया था, तो कोई भी व्यक्ति पूंजीपति कोयला, बिजली, सड़क, रेलवे और दूरसंचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों को स्थापित करने में रुचि नहीं रखता था, जहां लंबी निर्माण अवधि (Gestation period) के कारण तत्काल लाभ की गारंटी नहीं थी। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में पूंजीनिवेश करने की जरूरत थी। लेकिन ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की स्थापना के बिना, कोई भी पूंजीपति तत्काल लाभ कमाने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन और विपणन की स्थिति में नहीं होता।

इन हालात में, शासक एकाधिकारी पूंजीपतियों के वर्गीय हित साधते हुए भारत सरकार करों के जरिये जमा किये गए सार्वजनिक खजाने से वित्तपोषण के साथ प्रमुख क्षेत्रों को खोलने के लिए आगे आई। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) का विचार पैदा हुआ और आवश्यक प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में रेलवे का निर्माण किया गया। हालांकि इसे तथाकथित मिश्रित अर्थव्यवस्था (मिक्स्ड इकोनोमी) कहा गया, लेकिन नेहरूवादी आर्थिक नीति का मूल तत्व भारतीय पूंजीवाद का विकास ही था और वही काफी समय तक जारी रहा, जिससे रेलवे सहित विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां बनीं। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पूंजीवादी व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य भी बुर्जुआ वर्ग के हित साधना होता है। वास्तव में, भारतीय पूंजीवाद के विकास के क्रम में राज्य एकाधिकारी पूंजी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम विस्तार में जाने की बजाय संक्षेप में बात कर रहे हैं।

वैश्वीकरण ने नीतिगत बदलाव को चिन्हित किया

1990 के दशक में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के मोड़ पर, जब पूर्व सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों को प्रतिक्रांति और पूंजीवादी व्यवस्था की बहाली का सामना करना पड़ा, तो एक साम्राज्यवादी प्रभुत्व वाली एकध्रुवीय दुनिया उभरकर आई। नव औपनिवेशिक नुस्खों के साथ पूंजीवादी वैश्वीकरण (ग्लोबलाइजेशन) का नारा दुनियाभर में थोपा गया।

भारतीय शासक वर्ग ने साम्राज्यवादी गठबंधनों के एक अपेक्षाकृत कनिष्ठ भागीदार के रूप में भारतीय एकाधिकारी पूंजीपति घरानों की खुशी के लिए प्रमुख क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में निजीकरण की नीति अपनायी, जिन्होंने तब तक लाखों भारतीय लोगों का शोषण करके भारी संपत्ति जमा कर ली थी। उनके हाथों में मौजूद अतिरिक्त पूंजी निवेश के लाभदायक क्षेत्रों की तलाश में थी। जाहिर है कि भारतीय रेल कॉर्पोरेट घरानों के लिए मुनाफा कमाने का एक आकर्षक जरिया बन गई, वह भी आम जनता को सुरक्षित, किफायती और सुलभ यात्रा उपलब्ध कराने को ताक पर रखकर।

भारतीय रेलवे के निजीकरण का कार्यक्रम 1994 में पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस गठबंधन सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जो समग्र भूमंडलीकरण योजना का हिस्सा था। इसके बाद रेल मंत्रालय द्वारा कई उपाय अपनाये गए। पिछले 25 से 30 वर्षों के दौरान, सभी केंद्र सरकारों ने, चाहे वे किसी भी विचारधारा की हों, ''पुनर्गठन'', ''तर्कसंगतकरण'' और ''दक्षता में सुधार'' आदि के नाम पर भारतीय रेलवे के निजीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाया है।

चूंकि भारतीय रेलवे सबसे बड़ी सार्वजनिक इकाई है, इसलिए इसे एक झटके में पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपना मुश्किल है। इसलिए रेलवे संचालन के विभिन्न हिस्सों–रखरखाव, खान-पान (कैटरिंग), सफाई, सुरक्षा उपकरण और देखरेख–प्रत्येक हिस्से को अलग-अलग निगमों के अधीन लाया गया और फिर उन निगमों को अब एक-एक करके कॉर्पोरेट बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे को तोड़ने और निजीकरण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सबसे पहले दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में भाजपा-नीत गठबंधन सरकार द्वारा उठाये गए थे।

निजीकरण के प्रत्येक चरण को उचित ठहराने के लिए समय-समय पर कई समितियां गठित की गईं। इनमें भाजपा-नीत एनडीए सरकार द्वारा गठित राकेश मोहन समिति (2001), कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार द्वारा गठित सैम पित्रोदा समिति (2011) और वर्तमान मोदी-नीत भाजपा सरकार द्वारा गठित विवेक देबरॉय समिति (2014) निजीकरण की होड़ को आगे बढ़ाने में सबसे प्रमुख हैं।

योजनाबद्ध तरीके से निजीकरण

जैसा कि पहले कहा गया है, तर्कसंगतीकरण, पुनर्गठन और दक्षता में सुधार जैसे शब्दों की आड़ में, भारतीय रेलवे द्वारा पारंपरिक रूप से एक ही छत के नीचे प्रबंधित विभिन्न क्षेत्रों को निजी पूंजी के लिए खोला जा रहा है, जबकि कम लाभ वाले क्षेत्रों को अभी भी सरकार द्वारा चलाने के लिए छोड़ दिया गया है। राकेश मोहन समिति (2001) ने सिफारिश की कि भारतीय रेलवे को केवल माल और यात्री परिवहन की अपनी ''मुख्य गतिविधि'' (कोर एक्टीविटी) से सीधे संबंधित गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए, जबकि सभी ''गैर-मुख्य गतिविधियों'' को आउटसोर्स या कॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। सैम पित्रोदा समिति (2011) ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के नाम पर निजीकरण को और आगे बढ़ाया। हालांकि इसे साझेदारी कहा जाता है, लेकिन पीपीपी वास्तव में एक असमान व्यवस्था है, जहां निजी कंपनी को लाभ का आश्वासन दिया जाता है, जबकि सरकार जोखिम उठाती है। राज्य निजी पूंजी पर रिटर्न की दर की गारंटी देता है। अगर नुकसान होता है, तो वह अंततः जनता द्वारा वहन किया जाता है, जबकि लाभ निजी हाथों में जाता है। विवेक देबरॉय समिति (2014) ने लगभग पूर्ण निजीकरण की दिशा में बड़े कदमों की सिफारिश की। इन सिफारिशों के हिस्से के तौर पर अलग रेल बजट को समाप्त कर दिया गया, जिससे भारतीय रेलवे जैसे महत्वपूर्ण परिवहन क्षेत्र का विशेष दर्जा खत्म हो गया।

इसने भारतीय रेलवे को एक ट्रैक-होल्डिंग कंपनी और निजी ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली ट्रेन-ऑपरेटिंग कंपनियों में विभाजित करने की भी सिफारिश की। इसने यात्री और मालगाड़ी चलाने की ''मुख्य गतिविधियों'' को भी निजीकरण के लिए खोल दिया, जिससे केवल पटरियों का रखरखाव सरकार के पास रह गया, यहां तक कि इस ट्रैक रखरखाव को भी बड़े पैमाने पर निजी ऑपरेटरों को आउटसोर्स किया जाता है।

उन गतिविधियों को अलग करने के लिए लगभग दो दर्जन सार्वजनिक क्षेत्र के निगम बनाये गए हैं, जो गतिविधियां पहले भारतीय रेलवे द्वारा की जाती थीं। इनमें शामिल हैं: 1. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, 2. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी), 3. इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी), 4. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कोनकोर), 5. मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन (एमआरवीसी), 6. रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), 7. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन (केआरसीएल), 8. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल), 9. हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएसआरसीएल), 10. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 11. राइट्स लिमिटेड (आरआईटीईएस), 12. रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), 13. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसीएल) आदि। योजना के अनुसार इनका चरणबद्ध तरीके से निजीकरण किया जा रहा है।

जब 2021 में यात्री और मालगाड़ी चलाने की मुख्य गतिविधि का निजीकरण शुरू हुआ, तो 109 चयनित लाभदायक मार्गों पर 150 निजी यात्री ट्रेनें शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की गई। राजस्व कमाने वाले मार्ग निजी ऑपरेटरों को सौंपे जा रहे हैं, जबकि घाटे वाले खंड रेलवे के पास बने हुए हैं। रेल मंत्रालय ने 30% माल यातायात और 30% रेलवे स्टेशनों को निजी ऑपरेटरों को सौंपने की योजना की भी घोषणा की थी, जिसमें मुंबई सीएसएमटी स्टेशन जैसी प्रतिष्ठित विश्व विरासत भी शामिल है।

एक अन्य सिफारिश यह थी कि उन परियोजनाओं में निवेश नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें यातायात नहीं है और राजस्व उत्पन्न नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि निवेश केवल लाभ-गारंटी वाली परियोजनाओं में किया जाएगा, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों को रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के सामाजिक उद्देश्य को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, टिकटों की दरें समय-समय पर बढ़ायी जा रही हैं, अधिक शुल्क लेने के लिए पैसेंजर ट्रेनों का नाम बदलकर एक्सप्रेस ट्रेन किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म टिकटों की दरों में काफी वृद्धि की गई है–यह सब मुनाफे को अधिकतम करने की सिफारिशों पर आधारित है।

मोदी-नीत भाजपा सरकार पूर्ण निजीकरण की पक्षधर

मौजूदा भाजपा-नीत केंद्र सरकार की नीतियों ने रेलवे परिवहन के उद्देश्य को ही मौलिक रूप से बदल दिया है। आम लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के बजाय, सार्वजनिक धन को वंदे भारत, अमृत भारत, दुरंतो, तेजस और शताब्दी जैसी लक्जरी, हाई-स्पीड ट्रेनों की ओर मोड़ा जा रहा है, जो मुख्य रूप से मुट्ठीभर विशेषाधिकार प्राप्त अमीर वर्ग की सेवा करती हैं। एक वंदे भारत कोच की लागत नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों में उपयोग किये जाने वाले लिंक-हॉफमैन-बुश (एलएचबी) कोचों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। पैसेंजर ट्रेनें, जो सस्ती हैं और आम नागरिकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं, व्यवस्थित रूप से कम की जा रही हैं। स्लीपर किराये में वृद्धि के जरिये ज्यादा पैसा वसूलने के लिए द्वितीय श्रेणी के स्लीपर कोच हटाये जा रहे हैं और उनके स्थान पर एसी स्लीपर कोच लगाये जा रहे हैं। लगभग 90% स्लीपर कोचों को अब एसी कोचों में बदल दिया गया है। साधारण डिब्बे दूर के अतीत की बात हो गये हैं। नतीजतन, लोगों के एक बड़े तबके के लिए रेल यात्रा महंगी होती जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अक्सर मुंबई और अहमदाबाद के बीच 1.98 लाख करोड़ रुपये (17-24 बिलियन डॉलर) की लागत वाली बुलेट ट्रेन परियोजना का दावा करते हैं, जो देरी और लागत वृद्धि के कारण शुरुआती 1.1 लाख करोड़ रुपये के अनुमान से बढ़ गयी है। यह प्रोजेक्ट आखिर किसके लिए है? आम मेहनतकश जनता के लिए या अंबानी-अदानी और उनके जैसे अभिजात वर्ग के लिए?

निजीकृत ट्रेन संचालन के मॉडल का परीक्षण 2019 में आईआरसीटीसी के जरिये शुरू की गई दो निजी तेजस ट्रेनों पर किया जा रहा है। इसका किराया मांग के आधार पर दिन-प्रतिदिन बदलता रहता है, जैसा कि अब हवाई किराये के मामले में होता है। रेल कर्मचारियों को समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए अन्य ट्रेनों की कीमत पर निजी ट्रेनों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। स्टेशन मैनेजर, ट्रेन कंट्रोलर, लोको पायलट, गार्ड, सिग्नलिंग स्टाफ आदि जैसे ऑपरेटिंग स्टाफ को निजी ट्रेनों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कहा जा रहा है।

पहले रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवाएं आम लोगों के लिए आसानी से सुलभ और अत्यधिक सुविधाजनक थीं। आज इन सेवाओं को पट्टे (लीज) पर दे दिया गया है, जिससे अनियमितताएं, निजी दलालों द्वारा शोषण और धोखाधड़ी की प्रथाएं पैदा हो रही हैं। सार्वजनिक धन से विकसित प्रतीक्षा कक्ष (वेटिंग हॉल), सार्वजनिक शौचालय, पेयजल आपूर्ति और पार्किंग स्थल जैसी सुविधाओं को निजी ठेकेदारों को सौंपकर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये ठेकेदार अपना एक रुपया भी निवेश किये बिना जनता से भारी शुल्क वसूलकर मुनाफा कमाते हैं। इस प्रकार जनता के पैसे से निर्मित बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित रूप से बड़े कॉर्पोरेट ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है। निजीकरण से पहले, रेलवे खान-पान विभाग देशभर में बेस किचन संचालित करता था, जो अपेक्षाकृत बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराता था और एक लाख से अधिक मजदूर-कर्मचारियों के लिए रोजगार पैदा करता था। लेकिन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की शुरुआत के बाद इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। खान-पान का लाभ अब निजी ठेकेदारों द्वारा हड़पा जा रहा है। अकेले आईआरसीटीसी रोजाना लगभग 15 लाख का भोजन बेचता है, जिससे भारी मुनाफा होता है, जबकि मजदूर-कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी की जाती है। साथ ही, भोजन की गुणवत्ता में काफी गिरावट आयी है। खाने की चीजों में कीड़े और मरी हुई छिपकलियां तक मिल रही हैं। पैंट्री कारों में अनुबंध के आधार पर लगाये हुए मजदूरों को श्रम कानूनों के घोर उल्लंघन में लगातार कई दिनों तक काम करने को मजबूर किया जाता है।

कर्मचारियों में कटौती, सुरक्षा से समझौता

निजीकरण के उपाय लागू होने के बाद नियमित कर्मचारियों की संख्या में लगातार गिरावट आयी है। भारतीय रेलवे में 13,61,519 स्वीकृत पद थे। 2024 तक यह संख्या घटकर 12,52,180 रह गयी है। 2010 से 1,67,633 वर्कशॉप कारीगर पदों–जो स्वीकृत पदों का 57.7% है–को समाप्त कर दिया गया है। ये काम अब आउटसोर्स किये जाते हैं या अनुबंध के आधार पर नियुक्त मजदूरों से कराये जाते हैं।

इसी तरह, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की संख्या में भी काफी कमी की गई है। सिग्नलिंग, संचालन, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल विभागों में रिक्तियां बनी हुई हैं। लोको पायलट, ट्रैक मेंटेनर और ट्रेन मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

आजकल बच्चों को खिलाने-पिलाने के लिए भी पांच मिनट का अवकाश नहीं पाती हैं पार्वतियां

जून 1863 में लंदन के दैनिक पत्रों में प्रसिद्ध कपड़ा कंपनी की एक मजदूर बीस वर्षीय मेरी एन वाल्कले की मौत की खबर छपी थी। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक 'पूंजी' में इस मृत्यु का विवरण देते हुए लिखा था कि मेरी को औसतन साढ़े सोलह घंटे रोज काम करना पड़ता था, विशेष-विशेष समय पर बिना किसी अंतराल के अविराम तीस-तीस घंटे तक काम करना पड़ता था, जब उनकी श्रम शक्ति जवाब देने लगती, तो एक-आध बार थोड़ी कॉफी या कोई अन्य पेय पिलाकर उसे फिर काम में लगा दिया जाता था। युवरानी के सम्मान में नृत्य समारोह में भाग लेने वाली महिलाओं की पोशाक बनाने के लिए इस समय मैरी ने 60 अन्य लड़कियों के साथ काम करती थी। 30-30 लड़कियां एक-एक कमरे में बंद थीं, कमरा ऐसा कि जरूरत से एक तिहाई ही हवा मिलती थी। सोने का कमरा लकड़ी के तख्ते लगाकर छोटे-छोटे दमघोंटू कबूतरखानों में बांट दिया गया था। मेरी बीमार पड़ी और मर गई। डॉक्टर को बुलाने पर मेरी के शव की जांच करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी कि एक भीड़भरे कमरे में बहुत देर तक काम करने और एक बहुत ही छोटे, हवारहित कमरे में सोने के कारण मरी है।

हमारे भारत में 26 वर्षीय अन्ना सेबेस्टियन पेरेयिल की जुलाई 2024 में मौत हो गई। अन्ना को मेरी की तरह बंद कमरे में काम नहीं करना पड़ा, चकाचौंध वाले कॉर्पोरेट फर्म ने चार महीने में अन्ना के जीवन की रोशनी- हवा छीन ली। एक प्रतिष्ठित फर्म के पुणे स्थित कार्यालय में नौकरी पाकर प्रतिभाशाली छात्रा अन्ना बहुत खुश थी, उसने सोचा कि वह कार्यालय के अत्यधिक काम के बोझ को परिश्रम और निष्ठा से संभाल लेगी। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पायी। कार्यालय के समय के बाद, जब-तब, यहां तक कि आधी रात को भी फोन आने लगे और लगातार पहले से अधिक काम और भी अधिक काम का दबाव दिया जाने लगा। हर समय उसे कार्यालय की समय सीमा को लांघना पड़ता था। समय पर भोजन न करना, सोने में असमर्थता, दिन-रात गंभीर शारीरिक और मानसिक तनाव ने एक हंसती-खेलती लड़की की जान ले ली। फर्म के अधिकारियों को लिखे एक पत्र में अन्ना के शोकसंतप्त माता-पिता ने लिखा है कि कंपनी कर्मचारियों की जान जोखिम में डाल रही है, मुनाफे के लिए उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है और अति-ड्यूटी कराने को बहुत अच्छी चीज दिखा रही है। यह समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि यह किसी एक कंपनी की घटना या किसी व्यक्ति विशेष मालिक की अमानवीयता का मामला नहीं है। आजकल ऐसी खबरें अक्सर सुनने में आती हैं कि कई नामी कंपनियों के उच्च अधिकारी भी अत्यधिक काम के बोझ के चलते मानसिक तनाव-अवसाद से परेशान हैं या आत्महत्या कर चुके हैं, जो वास्तव में अमानवीय पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था द्वारा अंजाम दी गयी एक-एक हत्या है।

मेरी एन वाल्कले और अन्ना सेबेस्टियन पेरेयिल के बीच 161 साल का अंतर है, अंतर आर्थिक स्थिति का भी है, शैक्षिक योग्यता का भी। इन डेढ़ सौ वर्षों के दौरान, महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग के लिए कम संघर्ष नहीं किया। मेरी के समय में लड़कियों को शिक्षा का जो अवसर मिलता था, अन्ना को उससे कहीं अधिक मिला। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बावजूद, इस समाज ने अन्ना को जीने नहीं दिया। उस समय की मेरी और आज की अन्ना की मौत यह दिखाती है कि कैसे कारखाने के मजदूर से लेकर सफेद कॉलर के नौकरीपेशा तक, सभी घोर शोषण के शिकार हैं। ऊपर से लड़कियों के मामले में घर और बच्चों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी भी है, यौन उत्पीड़न है, पुरुषों की नजरों से बचना है।

सुभाष मुखर्जी की पुस्तक 'आमार बांग्ला' (मेरा बंगाल) में चटकल की मजदूर पार्वती को अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए कारखाने में पांच मिनट की भी छुट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए पार्वती बेटे को सुलाये रखने के लिए काम पर जाते समय उसके मुंह में अफीम डाल जाती थी, बेटा रोता नहीं था, बल्कि मुर्दे की तरह पड़ा सोता रहता था। एक साल पहले, उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल रीना ने एक बच्चे को अपनी छाती से बांध लिया था और पूरे दिन कुंभ मेले में भीड़भाड़ वाले स्टेशन पर ड्यूटी की। केंद्रीय बल में कार्यरत मां के बच्चे की जिम्मेदारी केवल उसकी है, न कि पुलिस-प्रशासन-राज्य की। बल्कि मीडिया के एक हिस्से ने एक मां की इस असहाय मजबूरी को 'मातृत्व की महिमा' के रूप में प्रचारित किया ताकि राज्य की अमानवीयता को छिपाया जा सके। वे माताएं, जो बच्चों को पीठ पर बांधकर सीढ़ी चढ़ रही हैं, घुटनों तक पानी में घुसकर मछलियां पकड़ रही हैं, पत्थर की खानों में काम कर रही हैं, वे महिलाएं, जो बच्चों को गोद में लेकर सुबह की ट्रेन पकड़कर शहर आ रही हैं, वे आशा बहनें, जो मामूली-से मानदेय के एवज में सुबह से शाम तक खटती हैं और उसकी भी महीनों से बकाया राशि नहीं पा रही हैं, वे जो महिलाएं घर के सारे काम खत्म करने के बाद रात में जागकर बीड़ी बनाते हुए तंबाकू के चूरे को फेफड़ों में भर रही हैं और तेन्दु के पत्तों की जहरीली हवा में सांस ले रही हैं—उनकी दिनचर्या में और भी भयानक वंचना, अन्याय और आंसू बहाने का इतिहास हर दिन, हर पल रचा जा रहा है। इसके बाद वे मां-बहनें थीं, जिनकी दिल दहला देने वाली लंबी आहें हर रात शहर-गांवों की अंधेरी गलियों में मिल जाती थीं। निर्भया, अभया, अपराजिता जैसी बाकी बची अनगिनत लड़कियां, जिनकी आंखें असमय बंद हो गयीं और जिनके खून से लथपथ हैं इस कलकत्ता, कामदुनी, कठुआ, दिल्ली, उन्नाव, हाथरस की सड़कें। सोशल मीडिया व अखबारों पर नजर डालने से पता चलता है कि ये खूंखार दरिंदें किसी को नहीं बख्शते हैं, न तो नवजात बच्ची को और न ही अस्सी साल की बूढ़ी महिला को! समाज तो लोगों का है, लेकिन घर, बाहर, बस-ट्राम, कार्यस्थल कहीं भी किसी लड़की को सुरक्षित रहने का भरोसा नहीं है।

इन सब दु:ख-दर्दों और गैर बराबरी को लेकर ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय कामकाजी महिला दिवस मनाया जाता है। हमें याद है कि मेरी एन वाल्कले जैसी हजारों महिला मजदूरों ने 8 मार्च, 1908 को न्यूयॉर्क की सड़कों पर काम करने की स्थिति में सुधार और काम के घंटे कम करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। 1910 में कोपेनहेगन में समाजवादी महिला सम्मेलन में जर्मन लेबर पार्टी की नेता क्लारा जेटकिन ने 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव रखा था, जो महिलाओं के शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ था। रूस की समाजवादी क्रांति के शिल्पी महान लेनिन ने इस दिन को महिला दिवस के रूप में मान्यता दी और समाजवादी रूस ने पूरी दुनिया के सामने नारी-मुक्ति की एक शानदार मिसाल पेश की। हमारे देश में भी संघर्षरत नारी समाज के लिए 8 मार्च जायज हक-हकूक और मान-सम्मान की मांग हासिल करने के लिए एकजुट होने का दिन बनता जा रहा है। आज इन्सान के तौर पर महिलाओं की जितनी उपलब्धियां हैं, समाज जितनी समानता उन्हें देने को बाध्य हुआ है, वह इस दिन के इतिहास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।

महिलाओं के प्रति अन्याय का इतिहास बड़ा लंबा है। खेती-बाड़ी के प्रचलन के जरिये स्थायी संपत्ति के आ जाने और वर्ग विभाजित समाज के कायम हो जाने के रास्ते ही एक दिन समाज में महिलाओं के दमन की शुरुआत हुई। महिलाओं को धीरे-धीरे संपत्ति की तरह घर में बांध दिया गया। दास प्रथा के बाद सामंती व्यवस्था को तोड़कर बुर्जुआ समाज ने अपने शुरुआती दौर में मनुष्यों के व्यक्तिगत अधिकारों के मुद्दे के साथ-साथ महिलाओं के समान अधिकार, समान सम्मान और मुक्ति की मांग को भी उठाया। लेकिन बुर्जुआ समाज एक प्रकार के शोषण की जगह दूसरे प्रकार के शोषण को लेकर आया। उसका उत्पादन लक्ष्य किसी भी कीमत पर मालिक का अधिकतम मुनाफा है। इसलिए समय के साथ, जैसे-जैसे यह पूंजीवाद अधिक मजबूत होता गया, इसकी प्रतिस्पर्धा जितनी ज्यादा तेज और एकतरफा होती गई, और भी मुनाफे के लिए इसने पुरुष और महिला दोनों का और अधिक शोषण करना शुरू कर दिया और शुरुआती लोकतांत्रिक चेतना से धीरे-धीरे हटते हुए घोर अलोकतांत्रिक हो गया। महिलाएं भी इस सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में मुनाफा कमाने का साधन हैं। इस समाज में महिलाएं एक तरफ जहां पूंजीवादी शोषण की शिकार हैं, वहीं दूसरी तरफ वे पुरुष-प्रधानतावादी उत्पीड़न की भी शिकार हैं। इसलिए आज की महिला का जीवन एक ही साथ दोहरे उत्पीड़न से ग्रस्त है। इस पूंजीवादी समाज के संचालक कुछ महिलाओं को उनके द्वारा अर्जित अधिकार देने को बाध्य होते हैं, लोकतंत्र का तमाशा बनाये रखने के लिए कुछ पुरुषप्रधानता-विरोधी प्रगतिशील नारे भी उन्हें देने पड़ते हैं, लेकिन महिला का वास्तविक सम्मान या मुक्ति वे बिल्कुल नहीं दे सकते। इसलिए जब भी हम इक्कीसवीं सदी के लगभग तीन दशक बीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप की जीत को देखकर खुशी से झूम रहे होते हैं, तो हमें महाराष्ट्र के बीड़ जिले की उन गन्ना किसान महिलाओं की याद आती है, जिन्हें मासिक धर्म के दौरान पानी की कमी से ग्रस्त होने के कारण बहुत कम उम्र में ही ऑपरेशन करवाकर अपना गर्भाशय निकलवाना पड़ा था। पढ़ाई और करियर में लड़कियों की भागीदारी और शानदार उपलब्धियों को देखकर जब भी हमारा मन खुशी से भर जाना चाहता है, तो उस खुशी को शिक्षा के दायरे से गायब हो रही अनगिनत लड़कियों के थके हुए चेहरे छुपा देते हैं। देश में हर सोलह मिनट में एक बलात्कार होता है, साथ ही देख रहे हैं सरकारी संरक्षण में शराब और ड्रग्स का धड़ल्ले से चल रहा कारोबार और फिल्मों व विज्ञापनों में नारीदेह की लगातार नुमाईश। महिलाओं को बेड़ियों में बांधने वाली जिन जंजीरों को अंदर-बाहर से तोड़ डालने का महिला दिवस का आह्वान था, वे अब प्रसाधन और गहनों पर छूट जैसी चीजें ही नारीत्व का उत्सव मनाने के प्रतीक बन गयी हैं। कन्याश्री, रूपश्री, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के विज्ञापन की चमक-दमक के पीछे वह अंधकारमय देश है, जो लैंगिक समानता के मामले में दुनिया के 193 देशों में 108वें स्थान पर है।

महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि नारी अधिकारों की लड़ाई सिर्फ आर्थिक मांगों को लेकर हीं नहीं है, बल्कि उस समाज के खिलाफ भी है, जो महिलाओं को मनुष्य बनने से हर तरह से रोकता है। राजा राममोहन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बेगम रुकैया, सवित्री फुले आदि ने महिलाओं को मानवीयता के प्रकाश में देखना चाहा। आज के जागरूक और मुक्तिकामी पुरुष-महिलाओं को यह साफ समझ लेना चाहिए कि पुरुष-प्रधानता पूंजीवादी शोषण का ही एक औजार है। अगर पुरुष-प्रधानता का बोलबाला वास्तव में खत्म करना है और खुला आसमान पाना है, तो सभी को इस पूंजीवाद के खिलाफ लड़ना होगा। ❑

भारतीय रेल : ...

(पृष्ठ 6 का शेष)

कर्मचारियों की कमी और दुर्घटनाओं में वृद्धि

कर्मचारियों की कमी के कारण कर्मचारियों को लगातार 12 से 20 घंटे काम करने को मजबूर होना पड़ता है। पर्याप्त आराम की कमी, मानसिक तनाव और थकान दुर्घटनाओं में योगदान देने वाले कारक हैं। स्थायी नौकरियों को अनुबंध श्रम से बदला जा रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि कर्मचारियों के वेतन ही वित्तीय दबाव के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्टें बताती हैं कि थकान और काम का दबाव दुर्घटनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

हाल ही में 72 मेल ट्रेन लोको पायलटों ने मंडल रेल प्रबंधकों को पत्र लिखकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) मांगी है, क्योंकि वे अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव, अनियमित कार्य स्थितियों और प्रशासनिक उच्चाधिकारियों के दबाव के कारण सेवा जारी रखने में असमर्थ हैं। सुरक्षा से संबंधित कार्यों में तैनात अनुबंध पर लगाये गये कर्मचारियों को अक्सर उचित प्रशिक्षण या सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किये जाते हैं, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। इसके अलावा, रेल दुर्घटनाएं अब एक आवधिक मामला बन गयी हैं। जून 2023 में ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना, जिसमें 288 लोगों की जान गई और 1,000 से अधिक यात्री घायल हुए, ने 'कवच' तकनीक की स्थापना के तमाम बड़े दावों के बावजूद रखरखाव और सुरक्षा तंत्र में गंभीर खामियों को उजागर किया।

रेल कर्मचारियों और यात्रियों की एकता अनिवार्य है

संक्षेप में, भारतीय रेलवे का निजीकरण 25 से अधिक वर्षों से सुनियोजित ढंग से चल रहा है और सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, हालांकि नाम के लिए शानदार वेतन और भत्तों वाला एक रेल मंत्री मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि निजीकरण अक्सर कर्मचारियों और यात्रियों दोनों को नुकसान पहुंचाता है। निजी ऑपरेटर लाभदायक मार्गों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कम व्यस्त मार्गों की उपेक्षा करते हैं। किराया बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जिससे आम लोगों की पहुंच सीमित हो जाती है।

भारतीय रेलवे के भविष्य को केवल मुनाफाखोरी के ख्याल से तय करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। बढ़ती कीमतों और घटती आय से परेशान आम लोगों की जरूरतें और हित न केवल प्राथमिकता, बल्कि एकमात्र उद्देश्य होने चाहिए। इसके लिए एक व्यापक सार्वजनिक बहस और निजीकरण की नीति के खिलाफ सामूहिक निरंतर आंदोलन की जरूरत है। सस्ती और सुरक्षित रेल परिवहन की रक्षा के लिए रेल कर्मचारियों और यात्रियों के बीच एकता जरूरी है। 1974 की विशाल रेलवे हड़ताल ने संगठित एकता की ताकत का प्रदर्शन किया था। जब श्रमिक और आम लोग संघर्ष के साधन के तौर पर जन कमेटियों का गठन करके एकजुट होंगे और पूरे देश में एक निरंतर आंदोलन खड़े करेंगे, तो यह निश्चित रूप से सरकार पर भारतीय रेलवे के बेरोकटोक निजीकरण को लागू करने से बाज आने का दबाव बनाएगा।●

PRGI Regn. No. 43022

पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य का तीन दिवसीय राजनैतिक शिक्षण शिविर सम्पन्न

पट्टी-प्रतापगढ़: शिक्षण शिविर का संचालन करते हुए कॉमरेड शंकर घोष

प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।

एसयूसीआई (सी) की पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य सांगठनिक कमेटी की ओर से 13 से 15 मार्च 2026 को यहां तीन दिवसीय राज्य स्तरीय राजनैतिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिक्षण शिविर का विषय था 'क्रांतिकारी जीवन ही है सबसे सम्मानजनक'। इस पुस्तक की रचना सर्वहारा वर्ग के महान नेता व प्रमुख मार्क्सवादी दार्शनिक कॉमरेड शिवदास घोष ने की है। शिक्षण शिविर की शुरुआत में कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद शिविर में भाग लेने वालों द्वारा रखे गये विभिन्न सवालों पर चर्चा हुई।

शिक्षण शिविर के दूसरे दिन 14 मार्च को विश्व सर्वहारा के महान नेता व महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स के स्मृति दिवस पर पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अरुण कुमार सिंह ने लाल झण्डा फहराया। तत्पश्चात केन्द्रीय कमेटी सदस्यों कॉमरेड स्वपन चटर्जी व कॉमरेड शंकर घोष व पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉमरेड रविशंकर मौर्य सहित अन्य नेताओं ने कार्ल मार्क्स की फोटो पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी।

राजनैतिक शिक्षण शिविर का संचालन एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी के सदस्यों कॉमरेड अरुण कुमार सिंह, कॉमरेड स्वपन चटर्जी व कॉमरेड शंकर घोष ने किया। नेताओं ने बताया कि विश्वभर में पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के बढ़ रहे हमले को रोकने के लिए साझा संघर्ष संगठित करने की जरूरत है। पूंजीवाद की चरम अवस्था अर्थात साम्राज्यवाद पतित होकर घोरतम अमानवीय कृत्य को अंजाम दे रहा है और बाजार संकट से निपटने के लिए विश्वभर में युद्ध की जमीन तैयार कर रहा है ताकि विभिन्न देशों में युद्ध सामग्री खरीदने के लिए ग्राहक मिल सकें। इस तरह की नापाक साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए मार्क्सवादी चिंतन ही एकमात्र क्रांतिकारी चिंतन है, जिसके आधार पर पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तेज किया जा सकता है।

पूंजीवाद की पतनशील संस्कृति के कुप्रभाव से बच्चों व छात्र-नौजवानों को बचाने का संघर्ष चलाना होगा। जिस तरह से समाज में आत्मकेन्द्रीयता, स्वार्थपरता, खुदगर्जी, लोभ-लालच, अवैज्ञानिक चिंतन, अंधविश्वास, दकियानूसी सोच, उपभोक्तावादी संस्कृति और धार्मिक कट्टरता की भावना बढ़ रही है, उसके प्रभावस्वरूप समाज में सांस्कृतिक गिरावट बढ़ती जा रही है। इसीलिए नारी सम्मान, बच्चों की सुरक्षा, सद्भाव, भाईचारा, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना व स्वस्थ सांस्कृतिक वातावरण कायम करने के लिए एकमात्र भरोसेमंद क्रांतिकारी रास्ता ही है, जिसकी जिम्मेदारी एसयूसीआई (सी) के नेता-कार्यकर्ताओं पर आ पड़ी है। यही समय की मांग है।

जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, दुःख-तकलीफ क्यों न उठानी पड़े, लाठी-गोली क्यों न खानी पड़े, लेकिन संघर्ष की इस राह में इन कठिनाइयों के साथ-साथ सही आनंद की सुखद अनुभूति, सही इज्जत व आत्मसम्मान पाने का सही रास्ता क्रांतिकारी जीवन में ही है।

क्रांतिकारी जीवन के लिए संघर्ष को तेज करने के लिए जनता के बीच रहना होगा, राजनैतिक समझ विकसित करनी होगी और राजनैतिक पहलकदमी करते हुए रचनात्मक कार्यों का सृजन करना होगा। इस तरह एक सही इनसान बनकर सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज करना होगा।

शिक्षण शिविर के अंत में 'अंतर्राष्ट्रीय गान' प्रस्तुत किया गया। इस तरह जोरदार नारों के साथ शिक्षण शिविर सम्पन्न हुआ।

तमिलनाडु में ...

(पृष्ठ 3 का शेष)

से व्यवसायीकरण और सांप्रदायीकरण करती है, विद्युत अधिनियम 2025, जो बिजली का निजीकरण करता है, चार नये श्रम कानूनों, जो श्रमिकों के अधिकारों को छीनते हैं और किसान विरोधी बीज अधिनियम के खिलाफ लड़ रही है। यह उन राज्य सरकारों के खिलाफ भी आवाज उठा रही है, जो इन्हें अलग-अलग नामों से लागू कर रही हैं।

इस राजनीतिक स्थिति में, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ने वाली एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने राज्य में चार विधानसभा सीटों से अपना प्रत्याशी उतारा है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) उम्मीदवारों को वोट देकर उन्हें विजयी बनायें ताकि विधानसभा में शोषित मेहनतकशों की आवाज सुनी जा सके।"

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवार

1. चेन्नई (आर.के.नगर)–कॉमरेड ए. मोहनराज
2. पेरंबूर – कॉमरेड जे. सेबेस्टियन
3. पेरियाकुलम –कॉमरेड जे. रंजीत कुमार
4. मदुरै (उत्तर)–कॉमरेड एम.जे. वाल्टेयर

पुडुचेरी विधानसभा— त्रिपुरा उपचुनाव में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवार

1. कामराज नगर – कॉमरेड एस. लेनिन दुरई
1. धर्मनगर –कॉमरेड संजय चौधुरी

एपस्टीन फाइल्स...

(पृष्ठ 5 का शेष)

और जेफरी एपस्टीन की साथी घिसलेन नोएल मैरियन मैक्सवेल को बाल यौन देह व्यापार का दोषी ठहराया गया है और उसे 20 साल की जेल की सजा सुनायी गयी है। इस प्रकार, एपस्टीन के खिलाफ मामलों से जुड़े दस्तावेजों और ईमेल के इस ताजा खुलासे के साथ फाइनेंसर द्वारा युवा लड़कियों के आपराधिक यौन शोषण और उसके अमीरों और ताकतवर हस्तियों से संबंधों के बारे में और भी जानकारी सामने आयी है–सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्लोवाकिया और भारत से भी।

पूंजीवाद से बहुत पहले का है यौन शोषण

यौन शोषण पूंजीवाद से बहुत पहले से मौजूद है। पूंजीवाद–जो शोषण और अधितम मुनाफा कमाने के उद्देश्य पर आधारित है, में यह निश्चित रूप से कम नहीं हुआ। पहले सार्वजनिक जीवन में इस पर कुछ सख्त प्रतिबंध हुआ करते थे। 1963 के अंत में ब्रिटिश राजनयिक जॉन प्रोफामो 20वीं सदी के ब्रिटेन के एक सबसे बड़े यौन कांड के केंद्र में थे। कहानियां प्रसारित हुईं कि उनका संबंध एक कमसिन उम्र की मॉडल, शो गर्ल और वेश्या क्रिस्टीन किलर से था, जो लंदन में ख्रुश्चेव के नेतृत्व वाले सोवियत संघ के सैन्य अधिकारी येवगेनी इवानोव से भी जुड़ी हुई थी। संसद में झूठ बोलने और इवानोव से मेलजोल के चलते सुरक्षा खतरा पैदा करने के कारण प्रोफामो को जून में मंत्रिमंडल और संसद दोनों से इस्तीफा देना पड़ा था, जिससे उसी वर्ष अक्टूबर में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार गिर गई। बाद में, जब व्हाइट हाउस की एक पूर्व इंटर्न मोनिका लेविंस्की ने दावा किया कि बिल क्लिंटन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रहते समय अपने पद का दुरुपयोग कर कई बार उनके साथ यौन संबंध बनाये, तब काफी हंगामा मच गया। इस आरोप के कारण बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई। उन्होंने पहले तो इससे इनकार किया, लेकिन बाद में स्वीकार करना पड़ा कि उनका उसके साथ "अनुचित संबंध" था। 1960 के दशक में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी और हॉलीवुड अभिनेत्री मर्लिन मुनरो के कथित विवाहेतर संबंध के आरोपों ने भी काफी तहलका मचा दिया था।

लेकिन अब एपस्टीन फाइल के सामने आने से यह एकदम स्पष्ट है कि कैसे मरनासन्न पूंजीवाद की वैश्विक धन-दौलत का चंद अमीरों के हाथों में संकेंद्रण, वैश्विक गतिशीलता, समुद्र-पार के देशों में वित्त और राजनीतिक दबदबा मिलकर यौन अपराधों को अंजाम देने वालों के दायरे को बढ़ाता है और उन्हें बचाता है। इस तरह यौन शोषण और यौन अपराध ने वैश्विक रूप ले लिया है और एक ताकतवर गठजोड़ के साथ संस्थागत भी हो गया है, जिसके तार पूरे विश्व में फैले हुए हैं। निजी जेट और द्वीप होना महज कोई इत्तफाक नहीं हैं; वे अपराधों और अपराधियों दोनों को सजा से बचाने के ढांचे हैं।

भारतीय संबंध

जारी किये गए दस्तावेजों में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले रिलायंस समूह के अरबपति अध्यक्ष अनिल अंबानी और एपस्टीन के बीच बातचीत का खुलासा हुआ है। ये बातचीत 2008 में यौन अपराधों के लिए एपस्टीन को हुई पहली सजा के बाद के वर्षों में हुई। दोनों ने भारत में आने वाले अमेरिकी राजदूतों से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कराने तक कई मुद्दों पर एक-दूसरे को ईमेल किये। यह संबंध व्यापार के मामले में भी परिलक्षित हुआ। किसी को याद होगा कि सितंबर 2016 में जब भारतीय और फ्रांसीसी सरकारों ने एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, जिसे "राफेल सौदे" के रूप में जाना जाता था, जिसमें अत्यधिक कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर शामिल थी, जिसके पास एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण बनाने का न तो कोई पूर्व अनुभव था और न ही विशेषज्ञता, यहां तक कि ऐसा करने के लिए उसके पास कोई कारखाना भी नहीं था। फिर भी राफेल जेट निर्माता फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी को दरकिनार कर रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इस तरह के पहले संयुक्त उद्यम के लिए भारी कर्ज में डूबी गैर-अनुभवी भारतीय फर्म को चुना।

एपस्टीन फाइलों में शामिल एक और बड़ा भारतीय नाम हरदीप सिंह पुरी का है, जो 2014 में भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त होकर भाजपा में शामिल हुए और फिर लोकसभा या राज्यसभा सीट जीते बिना ही मंत्री बने। जून 2014 से पुरी और एपस्टीन के बीच ईमेल का आदान-प्रदान हुआ। फिर दिसंबर 2014 में पुरी ने एपस्टीन को भेजे ईमेल में लिखा: "जब आप अपने विदेशी द्वीप से लौटें, तो कृपया मुझे बतायें" और उन्होंने एक मुलाकात तय करने को कहा, जिसमें पुरी एपस्टीन को कुछ किताबें दे सकते थे ताकि "भारत में रुचि जगाई जा सके"। जारी किये गए दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि पुरी ने एपस्टीन से उसके मैनहट्टन स्थित घर पर कम से कम तीन बार मुलाकात की थी: 4 फरवरी 2015, 6 जनवरी 2016 और 19 मई 2017 को। अपनी सफाई में पुरी ने भारतीय मीडिया को बताया कि एपस्टीन से उनकी मुलाकातें और बातचीत सिर्फ व्यावसायिक थीं।

निष्कर्ष

एपस्टीन फाइलें सिर्फ एक कांड नहीं हैं। ये भारत सहित विभिन्न देशों की राजनीतिक हस्तियों में धन-दौलत, राजनीतिक सत्ता और पतित बुर्जुआ संस्कृति के बीच पारगम्यता को भी उजागर करती हैं। एपस्टीन का सामाजिक दायरा अंतर्राष्ट्रीय था। वित्तीय वैश्वीकरण ने एक अनौपचारिक वैश्विक क्लब बना दिया है, जिसे धनकुबेरों का अनौपचारिक क्लब कहा जा सकता है–ऐसे लोगों का क्लब, जो सभा-सम्मेलन के मंचों पर नजर आते हैं, परोपकारी बोर्डों में हैं और पूंजी निवेशक हैं। ये नेटवर्क राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं और अक्सर नियामक ढांचे से आगे निकल जाते हैं। इससे यह भी उजागर हुआ है कि सेक्स रैकेट और नाबालिग लड़कियों को लेकर देह व्यापार एक जबरदस्त कमाई वाला धंधा बन गया है।

शासक पूंजीपति वर्ग और उसके राजनीतिक प्रबंधक कार्यकुशलता व खुशहाली का वादा करते हैं, लेकिन जब धन-दौलत का धनकुबरों के हाथों में संकेंद्रण चरम पर पहुंच जाता है, तो यह न्यूनतम कानूनी जवाबदेही व नीति-नैतिकता के बोध को भी खत्म कर देता है। यह अपराध व नैतिक पतन को बढ़ावा देता है और अपराधियों को संरक्षण देता है। वस्तुकरण तब तक बढ़ता जाता है, जब तक कि मानव भेद्यता भी शोषण योग्य पूंजी नहीं बन जाती।

एपस्टीन मर चुका है। उसकी सहयोगी मैक्सवेल जेल में है। लेकिन वे ढांचे, जिन्होंने उनको ऐसा करने में सक्षम बनाया–सकल वित्तीय अपारदर्शिता, अभिजात्य लोगों की एकजुटता और वर्ग शक्ति द्वारा आकार दिया गया अभियोगात्मक विवेक का अधिकार–अब भी बरकरार हैं। अगर इन फाइलों का वास्तव में कोई मतलब है, तो सिर्फ एक तमाशा नहीं, बल्कि संरचनात्मक आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए–महान मार्क्स और लेनिन द्वारा बतायी गई जरूरी शर्तें पूरी करने के बाद इस गये-गुजरे, सड़े-गले पूंजीवाद को क्रांतिकारी संघर्ष की चोट से उखाड़ फेंकना। अन्यथा, इन अपराधों के अभिलेख सिर्फ एक गिनती ही नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के दस्तावेज बनकर रह जायेंगे, जो जानबूझकर अपराधियों से सौदेबाजी करती थी और जुल्मो-सितम जारी रखती थी। ●

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**